दमण से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

Asli Azadi Dainik @AsliAzadiDainik asliazadidainikofficial

असली आज़ादी

The Voice of Union Territory Dadra and Nagar Haveli and Daman-Diu Since 2005 www.asliazadi.com

■ वर्ष: 21, अंक: 169 ■ दमण, बुधवार 25, मार्च 2026 ■ पृष्ठ: 8 ■ मूल्य: 2 रु ■ RNI NO-DDHIN/2005/16215 ■ संपादक- विजय जगदीशचंद्र भट्ट

मोदी सरकार का लोकसभा में खुलासा, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया जवाब

केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए नहीं बनेगा अलग यूटी मंत्रालय

■ केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि यूनियन टेरेटरी के लिए अलग मंत्रालय या नई नीति बनाने की कोई योजना नहीं है ■ संविधान के तहत मौजूदा व्यवस्था में ही योजनाएं चलाई जा रही है, मंत्रालयों के बीच समन्वय और संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति की निगरानी से विकास कार्य प्रभावी ढंग से आगे बढ रहे हैं: राज्य मंत्री नित्यानंद राय ■ दमण-दीव सांसद उमेश पटेल के सवाल के जवाब में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केन्द्रशासित प्रदेशों को लेकर चल रही अटकलों पर लगा दिया है पूर्ण विराम

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली 24 मार्च। पिछले कुछ समय से देश के केन्द्रशासित प्रदेशों को लेकर अलग यूटी मंत्रालय की चल रही अटकलों पर आज मोदी सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन पर सरकार ने साफ किया है कि अलग मंत्रालय या नई नीति बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संविधान के तहत मौजूदा व्यवस्था में ही सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालयों के बीच समन्वय और संसदीय समिति की निगरानी से विकास कार्य प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। नित्यानंद राय ने आगे बताया कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के तहत किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग मंत्रालय, विशेष समिति या नई नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि फिलहाल विभिन्न मंत्रालयों के बीच नियमित बातचीत और समन्वय से ही योजनाएं बनाई और लागू की जाती हैं। साथ ही, संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करती है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निर्दलीय सांसद पटेल उमेश पटेल के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। लिखित उत्तर में राय ने कहा कि सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रबंधन के लिए केंद्र शासित प्रदेश मामलों का अलग मंत्रालय या विभाग बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की निगरानी के लिए संसदीय निरीक्षण समिति गठित करने की भी कोई योजना नहीं है। उन्होंने दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष नीति ढांचा बनाने की संभावना से भी इनकार किया, भले ही उनकी भौगोलिक और प्रशासनिक आवश्यकताएं अलग हों।

लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसद उमेश पटेल ने दमण-दीव के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रदेश के हितों के लिए संसद में उठाई जोरदार आवाज

■ सांसद उमेश पटेल ने दमण-दीव में पूर्ण विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड और एम्स की स्थापना के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान की मांग की ■ सांसद ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी फीस कम करने या गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने, सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने, आयुष्मान योजना की सीमा बढ़ाने और सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज अनिवार्य करने की मांग की ■ सांसद उमेश पटेल ने जल संकट, औद्योगिक प्रदूषण, मछुआरों की समस्याओं, बुनियादी ढांचे के विकास, युवाओं के लिए खेल सुविधाओं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर भी दिया जोर ■ दमण-दीव को भारत की ब्लू इकोनॉमी का भविष्य बनाने के लिए सही निवेश और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है: सांसद उमेश पटेल

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली 24 मार्च। दमण-दीव के सांसद उमेश पटेल ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने संघ प्रदेश से जुडे महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती और विस्तार से सदन के सामने रखा। सांसद उमेश पटेल ने स्पष्ट कहा कि विकास का अर्थ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे प्रदेशों को भी समान अवसर और संसाधन मिलना आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रमुख मांगें रखते हुए सांसद उमेश पटेल ने बताया कि आज भी दमण-दीव में न तो कोई पूर्ण विश्वविद्यालय है और न ही अपना शिक्षा बोर्ड है। उन्होंने प्रदेश के लिए पूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विशेष वित्तीय प्रावधान की मांग की। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी फीस 15-25 लाख होने पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे कम किया जाए या गरीब एवं आदिवासी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाए। स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। इसलिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को प्रतिस्पर्धी वेतन एवं सुविधाएं दी जाएं। साथ ही पूरी तरह मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने हेतु बजट बढ़ाने की मांग की। उन्होंने आयुष्मान योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज अनिवार्य करने की मांग भी उठाई। एम्स, जल संकट और पर्यावरण पर जोर देते हुए सांसद उमेश पटेल ने कहा कि मुंबई से दक्षिण गुजरात तक कोई एम्स जैसी संस्था नहीं है इसलिए दमण में एम्स स्थापना हेतु विशेष फंड दिया जाए। उन्होंने दमण-दीव में हर वर्ष होने वाली पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए चेक डैम निर्माण और जल प्रबंधन के लिए विशेष बजट की मांग की। साथ ही वापी और आसपास के औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित दमणगंगा और कोलक नदी की स्थिति पर चिंता जताते हुए नमामि गंगे की तर्ज पर विशेष नदी पुनर्जीवन पैकेज की मांग की। मछुआरों और ब्लू इकोनॉमी के लिए विशेष पहल करते हुए सांसद उमेश पटेल ने कहा कि महंगे डीजल के कारण मछुआरे भारी संकट में हैं। गुजरात की तरह दमण-दीव में भी डीज़ल की बढ़ी कीमतें वापस ली जाएं। प्रति ट्रिप 5 बैरल की सीमा बढ़ाकर 10 बैरल की जाए। उन्होंने दमण-दीव को ब्लू इकोनॉमी का मजबूत केंद्र बताते हुए मछुआरों के हितों के लिए तत्काल राहत और नीतिगत समर्थन की मांग की। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए सांसद ने दमण और दीव में विकास परियोजनाओं की धीमी गति पर चिंता जताई और मांग की कि दीव में ड्रेजिंग और हार्बर प्रोजेक्ट शीघ्र शुरू हों, स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों हेतु केंद्र की बकाया राशि जारी हो, दमण गंगा पर नया नेशनल हाईवे ब्रिज बने, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले ब्रिज और ओवरब्रिज प्रोजेक्ट्स को गति मिले, साथ ही उदवाड़ा-दमण-वापी के बीच मोनोरेल परियोजना के लिए विशेष फंड की मांग की। युवाओं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर मांग करते हुए सांसद उमेश पटेल ने युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग और हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के नाम पर शोषण बंद हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन मिले, वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए और पेंशन दी जाए। कृषि और सामाजिक योजनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों की अनिच्छा के कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए दमण-दीव में फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सांसद उमेश पटेल ने अंत में कहा कि दमण और दीव केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की ब्लू इकोनॉमी का भविष्य बन सकता है। अगर सही निवेश और नीति समर्थन मिले, तो यह क्षेत्र राष्ट्रीय विकास का नया केंद्र बन सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इन सभी मुद्दों पर विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएं, तभी यह वित्त विधेयक वास्तव में जनहितकारी और समावेशी कहलाएगा। इसकी जानकारी दमण-दीव सांसद कार्यालय द्वारा प्रेसनोट जारी कर दी गई है।

दमण पुलिस ने अवैध काली फिल्मों के खिलाफ अपनाया जीरो टॉलरेंस नीति: कई स्थानों पर सघन चेकिंग के दौरान वाहनों ने निकाली काली फिल्म

■ दमण पुलिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए तेज की कार्रवाई ■ पुलिस ने नागरिकों से किया अनुरोध: सुरक्षा, पारदर्शिता और कानून के पालन के हित में पुलिस के साथ सहयोग करें और नियमों का पालन करें

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 24 मार्च। सुरक्षा, पारदर्शिता और कानून के अनुपालना के लिए दमण पुलिस ने अवैध काली फिल्मों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाया है। पुलिस की टीम विभिन्न मार्गों एवं मुख्य नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की जांच कर रही है और अवैध काली फिल्मों को गाडियों से हटाने का अभियान शुरु कर दिया है। इस बावत पुलिस द्वारा जारी प्रेसनोट में बताया गया है कि यह देखा गया है कि कुछ वाहन मालिक मौजूदा मोटर वाहन कानूनों का उल्लंघन करते हुए चार-पहिया वाहनों पर गहरे रंग के शीशे या बिना अनुमति वाली सन फिल्मों का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं। दमण पुलिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लागू कानूनी ढांचे के अनुसार, वाहन की खिड़कियों पर किसी भी ऐसी सामग्री (जिसमें रंगे हुए या काले रंग की फिल्में भी शामिल हैं) का इस्तेमाल करना, जिससे अंदर की दृश्यता कम हो जाती है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे उल्लंघन न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, प्रभावी पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम के लिए भी गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये वाहनों के अंदर की दृश्यता में बाधा डालते हैं। 1 जनवरी 2026 से अब तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल 216 चार-पहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। बिना अनुमति वाली फिल्मों को मौके पर ही हटवाया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त चालान जारी किए जा रहे हैं। दमण पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष अभियान और नाका चेकिंग चला रही है, साथ ही गश्त के दौरान लगातार निगरानी भी कर रही है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित मानकों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, बिना अनुमति वाली फिल्मों को हटाना और कानून के अनुसार अन्य कानूनी परिणाम शामिल हैं। जरूरत पडने पर वाहनों को जप्त (इम्पाउंड) भी किया जा सकता है। दमण पुलिस उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और उन्हें बिना किसी अपवाद के दंडित करने के लिए लक्षित अभियान जारी रखेगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षा, पारदर्शिता और कानून के पालन के हित में पुलिस के साथ सहयोग करें और नियमों का पालन करें। दमण पुलिस सडक सुरक्षा और प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

दीव जिले की वणाकबारा ग्राम पंचायत में हुई ग्रामसभा

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दीव 24 मार्च। दीव जिले की वणाकबारा ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में दीव जिला पंचायत उपप्रमुख नानजीभाई, सभी समाज के प्रमुखों एवं अग्रणियों, बोट एसो. के प्रमुख, ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं बडी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस ग्रामसभा के दौरान वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी दी गई। ग्रामसभा में गांव के विकास से जुडे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी विकास कार्यों की रुपरेखा तैयार की गई। वणाकबारा सरपंच वेलजी बिका की अध्यक्षता में आयोजित इस ग्रामसभा में अन्य जरुरतों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी महानुभावों एवं ग्रामीणों का पंचायत की ओर से आभार जताया गया।

विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा, राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है और सरकार 2032 तक सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देगी। उन्होंने कहा कि सरकार उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमजोर बताने के दावे को सीएम सुक्खू ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की गई है, बल्कि इस केवल छह महीने के लिए स्थगित किया है। साथ ही उन्होंने जयराम ठाकुर पर गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर कहा कि यदि सही आंकड़े दिखाते, तब स्थिति को लेकर भ्रम नहीं फैलता। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष सरकार के फैसलों का विरोध नहीं कर रहा और कोर्ट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि वे भी वास्तविक स्थिति को समझते हैं। इसके अलावा, उन्होंने सोलन और कुल्लू जिलों के अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की योजना की जानकारी दी, जिसके लिए लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मशीनें खरीदी जाएगी। अंत में सुक्खू ने सवाल उठाया कि कौन सी सरकार बेहतर है—वह जो 17 हजार करोड़ की आरडीजी से चल रही है या वह जिसने 76 हजार करोड़ के कर्ज का दुरुपयोग किया।

वजन घटाने वाली दवा को लेकर सतर्क ड्रग्स कंट्रोलर... दवा की बिना अनुमति बिक्री और प्रचार पर सख्त

नई दिल्ली (एजेंसी)। वजन घटाने वाली दवा (जीएलपी-1) की सप्लाई चेन में नैतिक फार्मास्युटिकल तरीकों को सुनिश्चित करने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने दवा की बिना अनुमति बिक्री और प्रचार के खिलाफ जांच तेज कर दी है। भारतीय बाजार में जीएलपी-1 आधारित वजन घटाने वाली दवाओं के कई जैनेरिक वेरिएंट के आने के साथ रिटेल फार्मेसियों, ऑनलाइन, थोक विक्रेताओं और वेलनेस क्लीनिकों के माध्यम से इसकी मांग को लेकर चिंता सामने आई हैं। जब इन दवाओं का उपयोग उचित चिकित्सकीय देखरेख के बिना किया जाता है, तब इनके गंभीर दुष्प्रभाव और संबंधित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। स्थिति का संज्ञान लेकर भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने राज्य रेगुलेटरों के सहयोग से फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में संभावित गलत तरीकों को रोकने और बिना अनुमति बिक्री तथा उपयोग को रोकने के लिए कई लक्षित कार्रवाइयां शुरू की हैं। 10 मार्च 2026 को सभी निर्माताओं को विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सरोगेट विज्ञापनों (अप्रत्यक्ष विज्ञापनों) और किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगाई गई थी, जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। हाल के हफ्तों में प्रवर्तन गतिविधियों को काफी बढ़ाया गया है। 49 संस्थाओं पर ऑडिट और निरीक्षण किए गए, जिसमें शामिल हैं ऑनलाइन फार्मेसी के गोदाम, दवा के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, और वेलनेस तथा स्लिमिंग क्लीनिक प्रमुख है। ये निरीक्षण देश भर के कई क्षेत्रों में किए गए और इनका मुख्य उद्देश्य बिना अनुमति बिक्री, गलत प्रिस्क्रिप्शन (दवा लिखने) के तरीके, और गुमराह करने वाले मार्केटिंग से संबंधित उल्लंघनों की पहचान करना था। रेगुलेटर इस बात पर ज़ोर देता है कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। चिकित्सकीय देखरेख के बिना वजन घटाने वाली दवाओं का गलत उपयोग गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी दवाओं का उपयोग केवल योग्य चिकित्सकों के मार्गदर्शन में ही करें।

देश के कई राज्यों में गुजरते मार्च में होगी बारिश और बर्फबारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश का असर है। राजस्थान में एक हफ्ते से बारिश और तेज हवा का अनुमान है। जो मार्च के अंत तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 31 मार्च के बीच राज्य में दो अलग-अलग ?वेदर सिस्टम सक्रिय होने वाले हैं। मध्यप्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर है। इसके कारण राज्य के उज्जैन, सागर, ग्वालियर-चंबल संभाग में बादल छाए। इसके कारण दिन के तापमान में गिरावट आई। 26-27 मार्च से आंधी-बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित 10 जिलों में बारिश हुई। यहां तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सिय या उससे भी नीचे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इससे 3-4 दिन तक पूरे प्रदेश में फिर बारिश हो सकती है। 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली गिरने की आशंका है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश की संभावना। वहीं 26 मार्च को मध्य भारत, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में पिछले सप्ताह शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर मार्च के अंत तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 26 से 31 मार्च के बीच दो अलग-अलग ?वेदर सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं जिलों में बारिश हुई। दोपहर में कोटा, बारां, अजमेर में बारिश हुई।

लालू को फिर झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका में कोई दम नहीं... ये कहकर खारिज की

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में स्थित दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में बड़ा झटका देकर उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने साफ कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। इस फैसले से लालू यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने दलील दी कि यह जांच ‘गैर-कानूनी और दुर्भावनापूर्ण’ है और उनके मुवक्किल के निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का हवाला देकर कहा कि बिना पूर्व मंजूरी के शुरू की गई जांच अवैध मानी जानी चाहिए। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन ली गई।

कपिल सिब्बल को फटकराते हुए सुप्रीम कोट... केवल 'ईडी,ईडी,ईडी' की रट मत लगाइये

सिब्बल से पूछा... क्या किसी सरकारी अधिकारी के मौलिक अधिकार नहीं होते

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण सवाल उठाकर पूछा है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं या केवल सरकारी अधिकारी होने के कारण वे अपने मौलिक अधिकार खो देते हैं? जस्टिस पी.के.मिश्रा और जस्टिस एन.वी.अंजारिया की पीठ ने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने मामले में व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की है। इसके बाद यह तर्क देना कि प्रवर्तन निदेशालय अनुच्छेद 32 के तहत याचिका नहीं दायर कर सकती। यह याचिका ममता बनर्जी पर राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ की गई तलाशी अभियानों में कथित हस्तक्षेप के आरोप में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, ÷क्या ईडी के अधिकारी हो जाने की वजह से देश के नागरिक नहीं रह जाते? उनके मौलिक अधिकारों का क्या?÷ पीठ ने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अदालत में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चेताया कि केवल ईडी,ईडी,ईडी÷ कहकर मामले को नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन अधिकारियों के अधिकारों पर ध्यान देना जरूरी है जो इस पूरे घटनाक्रम में कथित रूप से प्रभावित हुए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर कहा, कृपया ईडी के उन अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनके संबंध में अपराध किया गया है। अन्यथा, आप मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। आप उस दूसरी याचिका को नहीं भूल सकते, जिस याचिका को उन व्यक्तिगत अधिकारियों ने दायर किया है, जो इस अपराध के पीड़ित हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिर्फ ईडी, ईडी, ईडी की रट न लगाएं।

वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ

वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जांच करना कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में बाधा आती है, तब उसका समाधान कानून के तहत है, न कि अनुच्छेद 32 के जरिए होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी कानून की व्याख्या किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में करके, आपराधिक कानून की मूल विशेषताओं के विपरीत जाकर मुसीबतों का नहीं खोल सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी समय का हवाला देकर सुनवाई टालने की मांग भी खारिज की। जस्टिस मिश्रा ने कहा, ÷हम न चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, न किसी अपराध का। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और टालने के पक्ष में नहीं है।

पूरा मामला क्या है?

यह विवाद जनवरी में तब शुरू हुआ, जब ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि तब सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां से हटा लिए थे। ईडी का दावा है कि इससे उनकी जांच प्रभावित हुई। यह जांच कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी है, जिसमें कारोबारी अनूप माजी पर आरोप हैं।

अमेरिका और ईरान का तनाव कम करने के लिए भारत समेत 4 मुस्लिम देश हुए सक्रिय

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष को रोकने और इसे महायुद्ध में बदलने से बचाने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गई हैं। ताजा रणनीतिक घटनाक्रम और वरिष्ठ राजनयिकों से मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए ओमान और तुर्की के माध्यम से अत्यंत गोपनीय बैकचैनल वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। ऐतिहासिक रूप से मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ओमान ने एक बार फिर दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को संवाद की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनयिक हलकों में हो रही इन चर्चाओं से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस शांति प्रक्रिया में केवल तुर्की और ओमान ही नहीं, बल्कि भारत, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश भी लगातार कूटनीतिक संदेशों के आदान-प्रदान का जरिया बने हुए हैं। भारत के संबंध ईरान और अमेरिका दोनों के साथ संतुलित और बेहतर हैं, जिसे देखते हुए नई दिल्ली ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद के रास्ते खुले रखने में मदद की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन देशों की मध्यस्थता और कूटनीतिक दबाव ने युद्ध को अनियंत्रित होने से रोकने में एक सिक्योरिटी वाल्व की तरह काम किया है। हालांकि, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इन गुप्त वार्ताओं का हालिया घोषित 5-दिवसीय युद्ध विराम के फैसले पर कितना सीधा प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं। युद्ध के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही यह पहली बार देखा जा रहा है कि इतने सारे प्रभावशाली राष्ट्र एक साथ मिलकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा है कि आने वाले समय में कूटनीतिक समाधान की कोशिशें और तेज हो सकती हैं। कूटनीतिक गलियारों में यह दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशों के बाद भविष्य में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हो सकते हैं। फिलहाल, सैन्य तनाव के बीच इन गुप्त वार्ताओं ने वैश्विक स्तर पर शांति की नई उम्मीद जगाई है।

कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा

-दो सहयोगियों को भी 30-30 साल की जेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा

नसरीन को 30-30 साल की जेल की सजा दी गई। तीनों को इससे पहले जनवरी में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने पूर्व निर्णय में कहा था कि आसिया अंद्राबी और उसकी सहयोगियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहीं। 14 जनवरी को अदालत ने तीनों आरोपियों को यूएपीए की विभिन्न धाराओं-धारा 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना), धारा 38 (आतंकवादी संगठन से जुड़ाव) और धारा 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन) के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 120बी, 505 और 121ए के तहत भी इन्हें अपराधी पाया गया। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील ने कड़ी सजा की मांग की थी। एजेंसी का कहना था कि आरोपी देश के खिलाफ गंभीर साजिशों और गतिविधियों में शामिल रही हैं, इसलिए उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो समाज में एक कड़ा संदेश दे और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगे। गौरतलब है कि तीनों आरोपियों को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसे देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

राहुल गांधी एक अबोध बालक, वे एक नासमझ बच्चे की तरह हैं

-गिरिराज ने विपक्ष के नेता पर कसा तंज, बोले- मोदी के नेतृत्व पर सबको भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अबोध बालक बताया और उन पर कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी एक अबोध बालक हैं, वे एक नासमझ बच्चे की तरह हैं। मैंने जिक्र किया था कि कोविड काल में भी उनकी गतिविधियां देश में भ्रम फैलाने और लोगों को भड़काने से जुड़ी थीं। आज भारत के नेतृत्व और जनता को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने कोविड-19 के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। इस देश में अभी तक ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब राहुल गांधी की आवाज कहां है? वे दूसरी जगहों पर इस बारे में शोर मचाते रहते हैं, वे यह क्यों नहीं पूछते कि वहां कीमतें क्यों बढ़ाई गईं? भले ही देश के पीएम मोदी ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, जबकि अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने बढ़ा दी हैं, प्रबंधन का

मतलब ही यही है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत को किसी भी चीज से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत की जनता में अपार आत्मविश्वास है। हम किसी भी आपदा को अवसर में बदल सकते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। इस देश की एकमात्र समस्या विपक्ष का नेता (एलओपी) है।

गिरिराज यह टिप्पणी विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में पीएम मोदी के लोकसभा भाषण की आलोचना के बाद आई है, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अमेरिका का नाम न लेने का आरोप लगाया और कहा कि वह ट्रम्प के 100फीसदी नियंत्रण में हैं। राहुल ने कहा कि मैंने सुना है कि पीएम मोदी ने 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वे संसद में किसी बहस में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे समझौता कर चुके हैं। मोदी ने 25 मिनट तक भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। पीएम मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं।

राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने व्यापार समझौते के जरिए भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है और चेतावनी देते हुए कहा कि यहां हमारे पास छोटे खेत हैं, जबकि अमेरिका में हजारों एकड़ में फैले बड़े-बड़े खेत हैं। यहां लोग हाथों से काम करते हैं, और वहां बड़े-बड़े मशीनों से काम होता है। अगर अमेरिकी सामान भारत आने लगे, तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। ये टिप्पणियां पीएम मोदी के लोकसभा में अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष पर दिए गए भाषण के बाद आईं।

मोदी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य जाने वाला है

केजरीवाल बोले- आज चुनाव बेईमानी से जीते जा रहे, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है। उनका साम्राज्य जाने वाला है। केजरीवाल ने यह बात शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की किताब लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली में कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबक केजरीवाल ने कहा कि एक समय ऐसा होता था जब एक भी नेगेटिव कमेंट आता था तो इनकी पूरी मशीनरी मिलकर उसको डिलीट या म्यूट कर देती थी, लेकिन अब तो मोदी एक पोस्ट करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ गालियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब मोदीजी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी, लेकिन अब इतने मीम बन रहे हैं कि किस-किस को जेल में डालेंगे। सोशल मीडिया का पूरा माहौल और इको-सिस्टम ही बदल चुका है। वही आपको बताता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है।

बीजेपी के चुनाव जीतने पर केजरीवाल ने कहा कि चुनाव बेईमानी से जीते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। मेरे जेल जाने से पहले मेरी विधानसभा में जब मैं पिछली बार लड़ा था तो 1 लाख 48 हजार वोट थे। जब मैं जेल से लौटकर आया तो 1 लाख 6 हजार वोट बचे थे। 42 हजार वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह से जीत रहे हैं। वोट जोड़ते हैं, डिलीट करवाते हैं और फर्जी वोट डलवाते हैं। जब देश को इन दोनों से मुक्ति मिलेगी तो एक संतुष्टि यह होगी कि इस लड़ाई में हमने भी योगदान दिया और हम भी जेल गए थे।

इससे पहले केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से पैदा हालात को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में गिरावट है, एलपीजी की कमी से कई कारोबार प्रभावित हुए हैं और लोग गर्मी में सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है और रुपया भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। जब दुनिया को पहले से अंदेशा था, तो सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की और हर संकट का बोझ आम लोगों पर ही क्यों डाला जाता है।

अलवर: घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र की एसी फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान

अलवर (एजेंसी)। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित नीमराणा के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहाँ स्थित ट्रांस एचसीआर नामक एयर कंडीशनर (एसी) बनाने वाली कंपनी में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। रात के सन्नाटे में उठती आग की गगनचुंबी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता था, जिससे आसपास के ग्रामीणों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में भारी दहशत फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। नीमराणा, बहरोड़, घीलोठ और सोतानाला से दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि फैक्ट्री के भीतर एसी निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ज्वलनशील सामान,

प्लास्टिक पाट्र्स, पैकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भारी भंडार था। इस सामग्री ने ईंधन का काम किया, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई। गनीमत यह रही कि हादसा देर रात हुआ जब फैक्ट्री में श्रमिक मौजूद नहीं थे, जिसके कारण एक बड़ा जानी नुकसान टल गया।

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि फैक्ट्री की छत धधक उठी और परिसर के भीतर से रुक-रुक कर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री के अंदर रखे गैस सिलेंडर, कंप्रेसर या केमिकल कंटेनर अत्यधिक गर्मी के कारण फट गए, जिसने आग को और अधिक विकराल बना दिया। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस अग्निकांड में करोड़ों रुपये का कच्चा माल और कीमती मशीनरी जलकर राख हो गई है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है।

प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है, जो शॉर्ट सर्किट, मशीनरी में तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे बिंदुओं पर जांच करेगी। स्थानीय निवासियों और औद्योगिक संगठनों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की मांग की है। फिलहाल, सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

ईरान की रणनीति देख भारत ने भी पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट को ऑपरेशनल किया

-इस 'देसी ब्रह्मास्त्र' में है कम समय में भारी तबाही मचाने की क्षमता

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान की अमेरिका-इजराइल के खिलाफ चल रहे महायुद्ध ने इस चिंता को बढ़ा दिया है। इस वैश्विक तनाव और पाकिस्तान-चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के बीच भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने एक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट को ऑपरेशनल कर लिया है और इस साल के अंत तक एक और रेजिमेंट को शामिल करने की तैयारी में है। इससे सेना के पास अब 7 पिनाका रेजिमेंट हो गए हैं, जो पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं।

मीडिया रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों ने हवाले से बताया गया है कि पिनाका के आठवें रेजिमेंट के लिए अब आधे से ज्यादा उपकरण प्राप्त किए चुके हैं और 2026 के अंत तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। अगले साल दो और रेजिमेंट को शामिल करने की योजना है, जिससे कुल संख्या 10 हो जाएगी। भारतीय सेना का लक्ष्य 22 पिनाका रेजिमेंट बनाने का है, जिसमें नई लंबी दूरी वाली गाइडेड मिसाइलों से लैस संस्करण शामिल होंगे। ये पुरानी सिस्टम की जगह लेंगे और छोटे मिसाइल-ड्रोन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

भारत की पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा और चीन से सटी उत्तरी सीमा पर हालात लंबे समय से संवेदनशील रहे हैं। खासतौर पर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सेना ने अपनी आर्टिलरी ताकत को तेजी से मजबूत करने का फैसला लिया। भारतीय सेना ने तब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पॉवर और लार्सन एंड टुरबो के साथ करीब 2,580 करोड़ रुपए के छह पिनाका रेजिमेंट के लिए समझौता किया था। अब इनका तेजी से उत्पादन और तैनाती की जा रही है। ईरान-अमेरिका जंग में ड्रोन और मिसाइल स्वार्म अटैक की रणनीति देखते हुए सेना ने पिनाका को और अहम हथियार माना है। इस जंग में बड़े पैमाने पर रॉकेट, ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि भारत भी अपनी सेना को ऐसे हथियारों से लैस कर रहा है जो एक साथ कई लक्ष्यों को तेजी से निशाना बना सकें।

रिपोर्ट के मुताबिक पिनाका भारत का स्वदेशी मल्टी-बारेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस भारतीय सेना का 'देसी ब्रह्मास्त्र' कहा जाता है, क्योंकि यह कम समय में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। यह 122 मिमी रॉकेटों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और सटीक है। पिनाका 12 रॉकेट एक साथ दाग सकता है और कुछ ही सेकंड में दुश्मन के बड़े इलाके को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर तक है, जबकि इसके नए गाइडेड वर्जन 120 किमी तक सटीक हमला करने में सक्षम हैं।

आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन और लो-कॉस्ट मिसाइलें बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ भी प्रभावी माना जा रहा है। इसकी एक रेजिमेंट में 18-24 लॉन्चर होते हैं, जो मिनटों में सैकड़ों रॉकेट दाग सकते हैं। यह छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के स्वार्म अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ईरान की तरह दुश्मन अगर सस्ते ड्रोन और

मिसाइलों से हमला करे तो पिनाका का सैल्वो दुश्मन के लॉन्चर और कमांड सेंटर को पहले ही नष्ट कर सकता है। इसका एक रॉकेट महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है, जबकि दुश्मन की महंगी मिसाइल को रोकने वाले सिस्टम करोड़ों में होते हैं।

बता दें ईरान-इजरायल संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, जहां मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम अहम भूमिका निभाएंगे। भारत इसी दिशा में अपनी सेना को तैयार कर रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला किया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की रणनीति देखते हुए भारत ने सही समय पर कदम उठाया है।

आयुष मंत्रालय और डीबीटी ने आयुर्वेद में तपेदिक (टीबी) के उपचार में सहायक चिकित्सा के रूप में एक संयुक्त नैदानिक अध्ययन की घोषणा की

■ विज्ञान आधारित नवाचार और एकीकृत, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य देखभाल समाधानों द्वारा भारत में टीबी के विरुद्ध लड़ाई में तेज़ी आ रही है: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ■ तपेदिक उन्मूलन का अर्थ केवल संख्या कम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक रोगी स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति के साथ जीवन व्यतीत करे: आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव

नई दिल्ली (पीआईबी)। विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस के अवसर पर, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ साझेदारी में ₹आयुर्वेद में तपेदिक के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में नैदानिक अध्ययन₹ शीर्षक से एक सहयोगी नैदानिक अध्ययन की औपचारिक घोषणा के साथ एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में इस बारे में संयुक्त रूप से घोषणा की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माता, वैज्ञानिक, विद्वान, शोधकर्ता, चिकित्सक और अन्य महत्वपूर्ण हितधारक भी एकत्रित हुए, ताकि तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा सके।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ''भारत तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित तथा नवोन्मेषी प्रयासों के कारण तपेदिक के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।'' उन्होंने कहा, ''इस सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन का शुभारंभ विज्ञान-आधारित, साक्ष्य-आधारित नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आधुनिक जैव चिकित्सा अनुसंधान को मान्य पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में की गई पहलों के माध्यम से, हम अनुसंधान को मजबूत कर रहे हैं, वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दवा प्रतिरोध, कुपोषण तथा तपेदिक के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए रोगी-केंद्रित समाधानों को आगे बढ़ा रहे हैं।

आयुष मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहाः ''तपेदिक का उपचार केवल संक्रमण को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोगी को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के बारे में भी है। इस दृष्टिकोण के साथ, हम एक नए परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियाँ न केवल उपचार में सहायक हैं, बल्कि रोगियों के स्वास्थ्य लाभ, पोषण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।''कार्यक्रम का शुभारंभ डीबीटी के सचिव, बीआरआईसी के महानिदेशक और बीआईआरएसी के अध्यक्ष डॉ. राजेश एस. गोखले के उद्घाटन भाषण से हुआ। उन्होंने कहा, ''भारत में तपेदिक अनुसंधान ने निदान, टीकों और बड़े पैमाने पर किए गए विभिन्न अध्ययनों में नवाचार के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आयुष मंत्रालय के साथ यह सहयोगात्मक कार्यक्रम एकीकृत, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक विज्ञान को आयुर्वेद के साथ मिलाकर, हमारा उद्देश्य रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार करना, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और भारत के तपेदिक उन्मूलन मिशन को गति देना है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इसके बाद अपने विचार व्यक्त किए। श्री कोटेचा ने कहा, तपेदिक प्रबंधन के लिए न केवल प्रभावी उपचार बल्कि स्वास्थ्य लाभ और जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आयुष-डीबीटी की यह संयुक्त पहल साक्ष्य-आधारित एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है। आयुर्वेद को विज्ञान के साथ जोड़कर, हमारा उद्देश्य तपेदिक से संबंधित दुर्बलता को दूर करना, रोगियों के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना और भारत के तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य में सार्थक योगदान देना है। आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रबीनारायण आचार्य और बीआरआईसी-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई) के निदेशक डॉ. देबासिसा मोहंती ने सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तुति में अध्ययन की वैज्ञानिक रूपरेखा, उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसका उद्देश्य मानक तपेदिक रोधी उपचार (एटीटी) के साथ-साथ वृक्क पोषक तत्वों के पूरक के रूप में आयुर्वेद पद्धति की प्रभावकारिता, सुरक्षा और सहनशीलता का मूल्यांकन करना है। यह सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है, जो मई 2022 में एकीकृत और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित है। आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के नेतृत्व में और डीबीटी के सहयोग से संचालित यह बहु-केंद्रीय अध्ययन, पोषण संबंधी सहायता के साथ-साथ मानक तपेदिक-रोधी उपचार (एटीटी) के पूरक के रूप में आयुर्वेद उपचार की प्रभावकारिता, सुरक्षा और सहनशीलता का मूल्यांकन करेगा। एम्स, जेआईपीएमईआर और एनईआईजीआरआईएचएमएस सहित प्रमुख संस्थानों में आयोजित होने वाले इस 24 महीने के अध्ययन का उद्देश्य तपेदिक रोगियों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार, शीघ्र स्वस्थ होने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण जुटाना है, जिससे तपेदिक उन्मूलन के लिए नवीन, रोगी-केंद्रित दृष्टिकोणों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण ब्रिक-ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई) और सीसीआरएएस के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान था, जिसने संस्थागत सहयोग को औपचारिक रूप दिया। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान ब्रिक-टीएचएसटीआई के कार्यकारी निदेशक प्रो. जी. कार्तिकेयन और सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. वैद्य रबीनारायण आचार्य के बीच हुआ। कार्यक्रम का समापन भारत सरकार की जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए एकीकृत, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की दृढ़तापूर्वक पुष्टि के साथ हुआ। आयुष-डीबीटी सहयोगात्मक पहल से टीबी की सहायक देखभाल में नई वैज्ञानिक सुझाव और विचार प्राप्त होने की संभावना है, साथ ही बेहतर रोगी परिणामों और टीबी उन्मूलन की दिशा में त्वरित प्रगति के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक जैव चिकित्सा अनुसंधान के साथ जोड़ने में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों से एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ राज्यों में जटिलताएं रही हों, लेकिन कुल मिलाकर प्रक्रिया बिना बड़े विवाद के आगे बढ़ी है। सीजेआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन-जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, वहां यह सामान्य रूप से शांतिपूर्ण रही है। अन्य राज्यों में भी कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर मुकदमेबाजी नहीं हुई। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का सिद्धांत केवल पश्चिम बंगाल पर ही लागू किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और एआईटीसी नेता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदाता सूची फ्रीज करने की तारीख बढ़ाने पर विचार किया जाए, ताकि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनके दावों पर फैसला किया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेगा। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल चीजें ठीक चल रही हैं। इससे पहले 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें चुनाव आयोग पर एसआईआर के तहत दस्तावेज़ों के सत्यापन में लगे न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी करने का आरोप लगाया गया था।

महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर विशेष सत्र बुला सकती हैं मोदी सरकार

नई दिल्ली,(ईएमएस)। महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए मोदी सरकार की तैयारी जोरों पर जारी है। विपक्षी दलों के साथ भी मोदी सरकार बात कर रही है। इस बीच मंगलवार को विपक्षी दलों ने भी बैठक कर केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। यदि आप हमें विस्तार से बताया, तभी हम अपनी राय दे सकते और बताएंगे कि हम समर्थन कर पाएंगे अथवा नहीं। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री को खत लिखा है। अब खबर है कि केंद्र सरकार इस संबंध में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों को साधना चाहती है। इस कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं।

वहीं केंद्र सरकार के कुछ सूत्रों के हवाले से बताया गया हैं कि महिला आरक्षण के संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मोदी सरकार कई संभावनाओं पर फिलहाल विचार कर रही है। पहला यह कि सहमति बन जाए, तब इसी सत्र को बढ़ाकर बिल लाए जाएं। ऐसा ना होने पर फिर क्या विशेष सत्र लाया जा सकता है या फिर मॉनसून सेशन तक इंतजार किया जाए। दरअसल मोदी सरकार मसले पर जल्दबाजी में इसलिए भी दिख रही है, क्योंकि सीटें बढ़ने की स्थिति में परिसीमन होगा और चुनाव आयोग को लंबी मशक्कत करनी होगी। ऐसी स्थिति में कम से कम दो साल का समय चाहिए। 2026 का मार्च चल ही रहा है। यदि अब अगले कुछ महीनों में बिल को मंजूरी मिली, तब पूरी प्रक्रिया होते-होते 2029 के आम चुनाव करीब आ जाएंगे। इसके बाद मोदी सरकार पर्याप्त समय लेकर चलना चाहती है। किसी विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार ने फिलहाल 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा उसी के आधार पर सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इस कदम से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता भी दूर होगी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन से लेकर आंध्र में चंद्रबाबू नायडू तक इस पर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना था कि दक्षिण के राज्यों ने आबादी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। इसके बाद उनकी सीटों का अनुपात कम हुआ, तब यह जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लागू करने की एक सजा जैसा होगा। अब जब मोदी सरकार ने 2011 को ही आधार वर्ष मान लिया है, तब फिर दक्षिण के राज्यों को राहत मिली है। अब टीडीपी, वाईएसआर और डीएमके जैसे दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद है। खबर है कि लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों को 50 फीसदी बढ़ाया जाएगा। इस तरह कुल सीटों की संख्या 816 होने का अनुमान है और यूपी की संख्या 120 हो जाएगी। महाराष्ट्र से 72 सांसद और बिहार के 60 सांसद और इसी तरह बंगाल में सीटों की संख्या 42 से बढ़कर 63 हो जाएगी।

रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत की रक्षा तैयारियों पर इसके प्रभाव की समीक्षा की

नई दिल्ली (पीआईबी)। आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए, सीखे गए सबक, चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए अगले दशक के लिए एक एकीकृत रोडमैप को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना प्रमुखों, रक्षा सचिव, रक्षा उत्पादन सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष के साथ बैठक के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत की रक्षा तैयारियों पर इसके प्रभाव का जायजा लिया। उन्हें वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य, मौजूदा संघर्षों के संभावित विस्तार के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। मौजूदा उपकरणों के रखरखाव और सेवाक्षमता सहित रक्षा उपकरणों की खरीद और उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर स्थिति के प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया। रक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि भारत की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा संघर्ष से मिले परिचालन और तकनीकी सबक का निरंतर अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''हमें अगले दशक के लिए एक व्यापक एकीकृत रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें सीखे गए सबक, आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए सभी मोर्चों पर आत्मनिर्भरता और परिचालन तत्परता सुनिश्चित की जाए।

CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY NAME FROM **RATILAL LALJIBHAI TANDEL** TO RATILAL LALJI TANDEL
ADDRESS: 8/216, PARKOTA SHERI, NANI DAMAN-396210.

CHANGE OF NAME

OLD NAME:
KANCHANBEN LALLUBHAI TANDEL
NEW NAME:
KANCHANBEN HEMANTBHAI TANDEL
ADDRESS: H. No. 11/15, KOTHAPAT SHERI, KATHIRIA, NANI DAMAN, DAMAN - 396210.

संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

लोक निर्माण विभाग - दमन

निविदा आमंत्रण सूचना

दमन जिले में 6 पंचायत घरों की साज-सज्जा (भीमपोर, कडैया, दमनवाड़ा, परियारी, कचीगाम, दाभेल)(2nd Call)

टेण्डर ID सं :2026_DAMAN_4655_1

डाउनलोड करने की अंतिम तिथि :31/03/2026

हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि :31/03/2026

बोली खुलने की तिथि :31/03/2026

For details please scan

https://ddtenders.gov.in

प्रभारी कार्यपालक अभियंता,लो.नि.वि., जिल्ला पंचायत, मोटी दमण,

NO.IP/DMN/2/5/2025-26/1257 DATED: 24/03/2026

संघ प्रदेश दादरा एवम नगर हवेली और दमन एवम दीव प्रशासन/
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU,
समाहर्ता का कार्यालय, दीव/ OFFICE OF THE COLLECTOR, DIU.
Email: collector-diu-dd@nic.in
Phone:02875-252111

No.32-14-MAG/2025-26/ 3४९६ Dated :- 23/03/2026.

FORM NO.9

ORDER AUTHORISING AN ATTACHMENT OF PROPERTY BY THE DISTRICT MAGISTRATE OR COLLECTOR OF PERSON ABSCONDING UNDER THE GUJARAT PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES ACT, 1985 READ WITH SECTION 85 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023.

WHEREAS, complaint has been made before me that Zabbar Asif Movar, aged 31 years r/o 474 – A/2, Hajjpawada, Diu has been ordered to be detained under section 3(2) of The Gujarat Prevention of Anti-Social Activities Act, 1985 which is a deemed warrant of arrest u/s.8(1) of the Gujarat Prevention of Anti-Social Activities Act, 1985 thereupon issued that the said Zabbar Asif Movar cannot be found, and whereas, it has been shown to my satisfaction that the said Zabbar Asif Movar has absconded and thereupon a Proclamation had been duly issued and published requiring the said Zabbar Asif Movar to appear to answer the said charge within 30 days, and whereas the said Zabbar Asif Movar is in ownership of following Motor Vehicle Registration Nos.DD02[illegible], DD02F1100, DD02F2601, DD02D2457, DD02F[illegible], DD02F[illegible], DD02[illegible].

You are hereby authorised and requested to cause the said motor vehicles to be attached by seizing of above vehicles i.e. in the manner specified in clause (a) of sub-section(3) (a) of section 85, and to be held under attachment pending the further order of this Court, and to certify without delay what you may have done in pursuance of this order

Dated, this 23rd day of March, 2026.

(RAHUL DEV BOORA)
DISTRICT MAGISTRATE,
DIU.

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था

ललित गर्ग

आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना यह है कि जितने अधिक हथियार बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी ही असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में असुरक्षा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविश्वास का वातावरण बन जाता है। यह अविश्वास ही युद्ध की जमीन तैयार करता है।

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था आज मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर खड़ी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े जाने वाले संघर्ष नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, पर्यावरण, सृष्टि-संतुलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान और इजरायल के बीच हमलों का नया दौर, अमेरिका की रणनीतिक भूमिका, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान तनाव जैसे अनेक घटनाक्रम मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ और शक्ति संतुलन की राजनीति की ओर लौट रही है। यह स्थिति केवल राजनीतिक या सामरिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट का संकेत भी है, क्योंकि जब दुनिया हथियारों पर ज्यादा खर्च करती है तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं।

आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना यह है कि जितने अधिक हथियार बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी ही असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में असुरक्षा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविश्वास का वातावरण बन जाता है। यह अविश्वास ही युद्ध की जमीन तैयार करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और यह पैसा मानव विकास के बजाय विनाश की तैयारी में खर्च होगा। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए शुभ संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हमले, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव और बड़े देशों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी ने इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समुद्री मार्ग खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इजरायल पर हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिससे यह संकट और अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है।

दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर है और पश्चिम एशिया तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि वहां युद्ध बढ़ता है या समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और अंततः हर वस्तु महंगी हो जाएगी। यानी एक वैश्विक महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी जा सकती है। पहले से ही कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और यदि ऊर्जा संकट बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। भारत जैसे देश भी इस स्थिति से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। केवल केंद्र सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं होगी, राज्य सरकारों को भी इस स्थिति को समझते हुए ऊर्जा संरक्षण, आपूर्ति प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया युद्ध को रोकने के बजाय उसकी तैयारी ज्यादा कर रही है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन होता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध ऐसे हुए जो कुछ दिनों के लिए शुरू हुए लेकिन वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी यदि पश्चिम एशिया का युद्ध फैलता है तो यह केवल दो या तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की भागीदारी से यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि विश्व के बड़े देश आगे बढ़कर युद्ध विराम की पहल करें और वार्ता का रास्ता निकालें। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहे तो वह इजरायल पर दबाव डाल सकता है, ईरान के साथ वार्ता शुरू करा सकता है और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से युद्ध विराम की दिशा में कदम उठा सकता है। कूटनीति का रास्ता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध में अंततः नुकसान सभी का होता है। युद्ध में सैनिक मरते हैं, नागरिक मरते हैं, शहर बर्बाद होते हैं, अर्थव्यवस्था टूटती है और आने वाली पीढ़ियां तक उसके दुष्परिणाम झेलती हैं। इसलिए आज दुनिया को हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की दौड़ की जरूरत है।

हथियारों की होड़ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ा रही हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा हिस्सा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए तो दुनिया से गरीबी और भूख को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया की राजनीति अभी भी शक्ति संतुलन और सैन्य प्रभुत्व के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व नेतृत्व यह समझे कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास में होती है। जो देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली देश होता है। युद्ध और हथियार केवल विनाश लाते हैं, विकास नहीं। इसलिए दुनिया को यह तय करना होगा कि उसे हथियारों की दुनिया बनानी है या मानवता की दुनिया। यदि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध नहीं रुके और हथियारों की होड़ इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए खतरनाक होगी। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों के बारे में सोचें और युद्ध के बजाय शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएं। मानव सभ्यता का भविष्य हथियारों से नहीं, बल्कि शांति, संवाद और सहयोग से सुरक्षित हो सकता है। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।

युद्ध का अंधेरा मानवता को केवल विनाश, महंगाई, भय और अस्थिरता देता है, जबकि दुनिया को आज शांति, संवाद और स्थिरता का उजाला चाहिए, और इस दिशा में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज वैश्विक परिदृश्य में भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभरा है जो युद्ध नहीं, संवाद-संघर्ष नहीं, सहयोग और हिंसा नहीं, सहअस्तित्व की बात करता है। भारत बुद्ध, महावीर और गांधी की अहिंसा की परंपरा का देश है, इसलिए भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करे, युद्धरत देशों के बीच संवाद का सेतु बने, संयुक्तराष्ट्र के मंच पर युद्ध विराम की ठोस पहल करे, तो वह विश्व राजनीति को नई दिशा दे सकता है। मोदी यदि शांति, अहिंसा, वैश्विक संवाद और आर्थिक सहयोग के चार सूत्रों पर विश्व को साथ लाने की पहल करें तो भारत वास्तव में विश्व शांति का मार्गदर्शक बन सकता है और युद्ध की दिशा में बढ़ती दुनिया को शांति और स्थिरता की दिशा में मोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है।

संपादकीय

देर से आए और दुरुस्त नहीं आए

21 मार्च को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शाम साढ़े चार बजे के करीब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी कि रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी - ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे 'नॉर्मल' बताए, लेकिन हकीकत ये है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, लघु और अतिलघु उद्योगों (एमएसएमई) को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, विदेशी निवेशकों का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा, यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। और यह सिर्फ वक्त की बात है - चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मोदी सरकार के पास न दिशा है, न रणनीति - सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कह रही है- सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। शनिवार को लिखी इस पोस्ट के बाद नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को आकर संसद में मध्यपूर्व में चल रहे युद्ध पर सरकार के नजरिए को सामने रखा। हालांकि युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है और इस बीच संसद सत्र भी जारी ही था, तो प्रधानमंत्री के सामने पहले भी मौका था कि वे फौरन संसद से देश को संबोधित करते और बताते कि इस कठिन वक्त में वे देश को कौन सी राह पर आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहां भी उन्हें संभवतः इंतजार था कि राहुल गांधी कुछ कहें तो वे आगे बढ़ें। हमेशा यही होता है। राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं, सरकार पहले उनका मजाक उड़ाती है, बाद में उसी पर आगे भी बढ़ती है। जाति जनगणना को स्वीकार करना या किसान आंदोलन में आखिरकार मानना कि कोई कमी रह गई है ये सब उसी के उदाहरण हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने सोमवार को जो कुछ संसद में कहा, उससे देश की मौजूदा समस्याओं के हल को लेकर कोई आस नहीं बंधी, दूसरी तरफ इस युद्ध को लेकर जो स्पष्ट नजरिया उन्हें रखना चाहिए था, उसमें भी वे चूक गए। युद्ध सही नहीं है या संवाद से समाधान निकालें, जैसे उपदेश देने का वक्त अब नहीं रहा। बल्कि नरेन्द्र मोदी के सामने पूरा मौका था कि वे अपनी संसद में, अपने ही लोगों के बीच, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के दायरे में अमेरिका और इजरायल को कहते कि ईरान पर युद्ध छेड़कर आपने ठीक नहीं किया। आपको किसी देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है। नरेन्द्र मोदी ऐसा करते तो शायद आज विपक्ष भी उनके साथ ही खड़ा होता और इससे पूरी दुनिया में भारत की आवाज फिर से बुलंद होती।

चिंतन-मनन

अंतर्दृष्टि से अनुबंधित है ज्ञान

बुद्धि अच्छी चीज है, पर कोरी बौद्धिकता ही सब कुछ नहीं है। इससे व्यक्ति के जीवन में नीरसता और शुष्कता आती है। ज्ञान अंतर्दृष्टि से अनुबंधित है, इसलिए यह अपने साथ सरसता लाता है। ज्ञानी व्यक्तियों के लिए पुस्तकीय अध्ययन की विशेष अपेक्षा नहीं रहती। भगवान महावीर ने कब पढ़ी थीं पुस्तकेंट आचार्य भिक्षु, संत तुलसी, संत कबीर अदि जितने ज्ञानवान पुरुष हुए हैं, उनमें कोई भी पंडित नहीं थे। अंतर्दर्शन उनकी ज्ञानमयी चेतना की स्फुरणा करता था। इसके आधार पर ही उन्होंने गंभीर तत्वों का विश्लेषण किया। वे यदि पुस्तकों के आधार पर प्रतिबोध देते तो संसार को कोई नया दृष्टिकोण नहीं दे सकते थे।

एक बात और ज्ञातव्य है। विद्वान बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, पर वे आज तक भी किसी ज्ञानी को पराजित नहीं कर सके। इंद्रभूति महापंडित थे। उनका पांडित्य विश्रुत था। पर वे भगवान महावीर की ज्ञान चेतना का अनुभव करते ही पराभूत हो गए। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। ज्ञान और बुद्धि की परस्पर कोई तुलना नहीं है। बुद्धि कुंड का पानी है और ज्ञान कुएं का पानी है। कुंड का पानी जितना है उतना ही रहता है। वर्षा होती है तो पानी थोड़ा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अनुकूल सामग्री और पुरुषार्थ का योग होता है तो बुद्धि बढ़ जाती है। अन्यथा उसके विकास की कोई संभावना नहीं रहती। कुएं से जितना पानी निकाला जाता है, नीचे से और आता रहता है। वह कभी चुकता नहीं है, उसमें नए अनुभव जुड़ते जाते हैं।

बुद्धि आवश्यक है किंतु उसके आधार पर कभी आत्म-दर्शन नहीं हो पाता। आत्म-दर्शन का पथ है ज्ञान। ज्ञान तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक ध्यान का अभ्यास न हो। जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि का उद्घाटन करना है, ज्ञानी बनना है, उसे प्रेक्षाध्यान साधना का आलंबन स्वीकार करना होगा। ऐसा करके वह ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर सकता है।

ऊर्जा ठिकानों पर हमलेः दुनिया को मंदी की ओर धकेलता युद्ध

राज कुमार सिन्हा

ईरान के साऊथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर यह हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। आपूर्ति में रुकावट के कारण कई देशों को लंबे समय तक ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार अंतराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इतिहास का सबसे खराब वैश्विक ऊर्जा व्यवधान बताया है, जो 1973 के अरब तेल प्रतिबंध को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्य निवेश अधिकारी डैन पिकरिंग ने कहा कि आप ऊर्जा संरक्षण के जरिए इस समस्या से बच नहीं सकते। इसका नतीजा यह होगा कि कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग उपभोग करना बंद कर देंगें। यह पहली बार है जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान के ऊर्जा ढांचे को सीधे निशाना बनाया गया है। 17 मार्च तक, अमेरिका और इजराइल ने खाड़ी में ईरान के ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाने से परहेज किया था। यहां तक कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के 90 प्रतिशत तेल निर्यात के केंद्र खारग द्वीप पर हमला किया, तब भी केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। इजराइल द्वारा कतर के साथ साझा किए जाने वाले साऊथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के बाद यह स्थिति बदल गई है। पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। इस घटना को अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को बड़े ऊर्जा संकट के रूप में देखा जा रहा है। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी के साथ-साथ कतर और यूएई में गैस सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यह युद्ध का एक खतरनाक मोड़ साबित हो रहा है। साउथ पार्स गैस क्षेत्र, भारत सहित वैश्विक एलएनजी आपूर्ति की रीढ़ है। इजरायली हमले के बाद तेल और गैस की कीमतों में आई तत्काल वृद्धि से इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने के कारण दुनिया पहले से ही कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान से जूझ रही है। ऐसे में उत्पादन सुविधाओं को होने वाली किसी भी क्षति का प्रभाव वर्षों तक बना रह सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रही बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि एक छोटा समुद्री मार्ग भी वैश्विक सप्लाई चेन को हिला सकता है। कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है, ईरानी मिसाइल हमलों से तबाह हो गया है। रास लाफान पर हमलों के कारण कतर की कुल एलएनजी निर्यात क्षमता में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है। कतर एनर्जी के अधिकारियों के अनुसार, इस नुकसान की मरम्मत में 3 से 5 साल का समय लग सकता है, जिससे यह एक दीर्घकालिक संकट बन गया है। इस हमले से कतर को प्रति वर्ष लगभग 20 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।

यह हमला केवल कतर तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस जरूरतों का लगभग 40 से 50 प्रतिशत कतर से आयात करता है, इसलिए यह स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। मध्य पूर्व से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को तेल का लगभग 75 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का 59 प्रतिशत निर्यात होता है।

इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को तेल-गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन और उत्पादन जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने कहा है कि खाद्य सेवा उद्योग का 75 फिसदी हिस्सा एलपीजी पर निर्भर है और लंबे समय तक इसकी कमी रहने से अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 12 से 13 हजार करोड़ रुपए नुकसान हो सकता है। युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 39 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं। ईंधन और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में माल ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए और इंडस्ट्रियल डिजल 22 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है। दुनिया भर में यूरिया की कुल आपूर्ति में कतर का लगभग 10 प्रतिशत योगदान है। लेकिन ईरानी हमले की वजह से कतर के कई प्लांट बंद हैं, जिससे भारत में भी खाद की किल्लत बढ़ सकती है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि ने वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान घटाए हैं। विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह कम हुआ है। कई देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ा दिए हैं, जिससे सामाजिक और विकासात्मक खर्चों पर दबाव बढ़ा है। भारत सहित वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन सप्ताह में 27 से 34 लाख करोड़ रुपये तक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं। मूडीज के अनुसार, ऊर्जा की कीमतें बढ़ती रहीं तो भारतीय रुपये पर दबाव और बढ़ेगा। खाडी देशों में 90 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। युद्ध के कारण 50 हजार भारतीय वापस देश लौट चुके हैं। अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो काम प्रभावित होगा और शेष भारतीय भी वापस लौटने को मजबूर होंगे। खाडी देशों में भारतीय काम करके अच्छा खासा रेमिटेंस भारत में भेजते हैं। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि यदि संघर्ष जारी रहता है, तो कतर और कुवैत की जीडीपी में 14 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। यह विदित है कि युद्ध के कारण अनिश्चितता बढ़ती है, जिससे निजी निवेश रुक जाता है और वित्तीय प्रणाली कमजोर होती है। युद्ध राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचे के विनाश और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में गिरावट का कारण बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए 100 से अधिक युद्धों के अध्ययन में यह पाया गया कि इन संघर्षों के कारण संबंधित देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़े। वर्तमान युद्धों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुआयामी संकट में डाल दिया है। यदि यह संघर्ष जल्द समाप्त नहीं होता, तो यह 1990 के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक बन सकता है। यह संकट दुनिया भर के उपभोक्ताओं, व्यवसायों और नीति निमार्ताओं के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और वैश्विक मंदी के जोखिम को बढ़ा रहा है।

ईंधन की कमी से जूझ रही दुनिया, हर देश के सामने संकट, पाबंदियों के चलते जनता बेहाल

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात के चलते दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां तेल केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि सत्ता, रणनीति और अस्तित्व का सवाल बन चुका है। ताजा हालात बता रहे हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने देशों को झकझोर कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कीमतें करीब बत्तीस प्रतिशत उछलीं, पाकिस्तान में पच्चीस प्रतिशत और अमेरिका में चौबीस प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी ने साफ कर दिया है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का संकेत है। जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन से लेकर जापान तक हर देश इस आग में झुलस रहा है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारें अब सीधे जनता की जिंदगी में दखल दे रही हैं। पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, चार दिन का कार्य सप्ताह लागू किया गया और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधा काम घर से करने का आदेश जारी हुआ। गैर जरूरी सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाया गया और ईंधन आवंटन में पचास प्रतिशत कटौती कर दी गई। यह कदम साफ दिखाता है कि संकट कितना गहरा है।

श्रीलंका ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। स्कूल, विश्वविद्यालय और गैर जरूरी दफ्तर बंद कर दिए गए। क्यूआर आधारित ईंधन पास फिर से लागू कर दिया गया, जिसमें निजी वाहनों के लिए साप्ताहिक सीमा तय कर दी गई। यह व्यवस्था बताती है कि सरकारें अब संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का सहारा ले रही हैं। बांग्लादेश में विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए और ऑनलाइन शिक्षा लागू की गई। पांच घंटे की बिजली कटौती ने आम जीवन को झकझोर दिया है। उर्वरक संयंत्र तक बंद करने पड़े, जिससे कृषि और खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। भूटान में जमाखोरी रोकने के लिए जरी कैन में ईंधन बिक्री पर रोक लगा दी गई और आपात सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

फिलीपींस और वियतनाम में भी हालात काबू से बाहर जाते दिख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए चार दिन का कार्य सप्ताह और निजी क्षेत्र को घर से काम करने की सलाह दी गई है। गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाकर सरकारें साफ संकेत दे रही हैं कि अब हर बूंद की कीमत है।

अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में संकट और भयावह है। म्यांमार ने निजी वाहनों के लिए विषम सम प्रणाली लागू कर दी। कंबोडिया में हजारों पेट्रोल पंप बंद हो गए। लाओस में सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम और रोटेटिंग शिफ्ट लागू की गईं ताकि आवागमन कम हो। दक्षिण अफ्रीका में नियंत्रित आवंटन लागू हो चुका है, जबकि मिस्र में बाजार, रेस्तरां और सरकारी दफ्तरों के समय सीमित कर दिए गए और रोशनी वाले विज्ञापन बंद कर दिए गए।

वहीं केन्या ने ईंधन राशनिंग और निर्यात पर प्रभावी रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड में हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों में भी डीजल खरीद पर सीमा तय कर दी गई है। इस तरह यह संकट अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है।

देखा जाये तो यह तेल संकट केवल कीमतों का खेल नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया अध्याय है। ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण रखने वाले देश अब निर्णायक बढ़त हासिल कर रहे हैं। जो देश आत्मनिर्भर नहीं हैं, वे नीतिगत गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, राशनिंग और आवागमन पर नियंत्रण जैसे कदम बताते हैं कि सरकारें अब युद्धकालीन नीतियों को शांतिकाल में लागू कर रही हैं।

इसके अलावा, यह संकट आने वाले समय में कई बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। एक तो, ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बनेगी। इसके अलावा, डिजिटल निगरानी और संसाधन नियंत्रण बढ़ेगा, जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, आपूर्ति श्रृंखला टूटने से खाद्य संकट और महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। सबसे अहम बात यह है कि यह संकट देशों को मजबूर कर रहा है कि वह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ें। लेकिन जब तक यह बदलाव पूरी तरह नहीं होता, तब तक जनता को कड़े प्रतिबंध और कठिन फैसलों का सामना करना ही होगा। बहरहाल, तेल संकट ने दुनिया को आईना दिखा दिया है। यह साफ है कि आने वाले समय में ऊर्जा ही असली शक्ति होगी। सरकारें जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझेंगी, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल, हालात यह कहते हैं कि दुनिया एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां हर देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल की नदी में दो भारतीय किशोर लापता

पालपा, एजेंसी। नेपाल के पालपा जिले में रविवार को एक नदी में तैरते समय भारत के दो किशोर कथित तौर पर बह गए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले 17 वर्षीय फरान अंसारी और अमन अंसारी तिनाऊ नदी में तैरते समय लापता हो गए। सरकारी दैनिक गोरखापत्र ने पालपा जिला पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। ये दोनों किशोर भारत से आए सात युवकों के एक समूह का हिस्सा थे, जो तानसेन नगरपालिका के तिनाऊ नदी तट पर आए थे। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी होम प्रकाश चौधरी ने बताया कि उनमें से दो नदी के बहाव में बह गए। तलाशी अभियान शुरू किया गया लेकिन रविवार शाम तक कोई नहीं मिला। यह नदी नेपाल और भारत के तैराकों के बीच प्रसिद्ध है और कई लोग यहां मनोरंजन के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस नदी में इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

इस्तांबुल में गैस विस्फोट के कारण दो इमारतें ढहने से एक शख्स की मौत

फातिह, एजेंसी। इस्तांबुल के मध्य फातिह जिले में प्राकृतिक गैस विस्फोट के कारण रविवार को दो इमारतें ढह गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार खोज और बचाव कर्मियों ने 10 घायलों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। राज्यपाल दावुत गुल ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में बचे लोगों का हालचाल पूछा।

वेस्ट बैंक में चार फलस्तीनियों की मौत के बाद गाड़ियां में तोड़फोड़ और आगजनी

वेस्ट बैंक , एजेंसी। इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राइली बस्तियों में रहने वालों ने शनिवार की रात और रविवार की सुबह कई फलस्तीनी गांवों में उत्पात मचाया। इन लोगों ने कारों को तोड़ा, उनमें आग लगाई और कई लोगों को घायल कर दिया। फलस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा ने रविवार को कम से कम छह समुदायों में हुए हमलों की सूचना दी। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि जलुद गांव में कम से कम तीन फलस्तीनियों को मारपीट से सिर में चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बस्तीवासियों का सामना किया, जिनमें से कुछ घायल हो गए। यह हिंसक घटना उस दिन के एक दिन बाद हुई जब दो गांवों के पास के इलाके में एक फलस्तीनी वाहन से टक्कर में 18 वर्षीय इस्राइली निवासी की मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि वे निवासियों के इस दावे की जांच कर रहे हैं कि टक्कर जानबूझकर की गई थी। गौरतलब है कि इस्राइली सरकार वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाने का काम भी आगे बढ़ा रही है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से हिंसा में व्यापक वृद्धि के साथ-साथ बस्तियों में बसने वालों के हमले भी तेज हो गए हैं। इससे पहले अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इस्राइली हमलों में चार फलस्तीनी मारे गए।

हमलों के बीच ईरान का बयान: होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं, पर सुरक्षा नियम सख्त

तेहरान , एजेंसी। अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है और इस जलमार्ग में नौवहन जारी है। हालांकि, उसने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और बचाव का सम्मान किया है। उसने सालों से इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य हमलों के बाद खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जिसका सीधा असर क्षेत्रीय समुद्री सेफ्टी और सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। आत्मरक्षा के अपने कानूनी अधिकार का दावा करते हुए ईरान ने कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाया है। साथ ही, उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि आक्रमणकारी और उनके समर्थक देश के खिलाफ अपने मकसद को पूरा करने के लिए स्ट्रेट का गलत इस्तेमाल न कर सकें। ईरानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसने आक्रमणकारियों से जुड़े या उनके साथ संबद्ध जहाजों के गुजरने को अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत रोका है। उसने कहा कि दूसरे देशों के या उनसे जुड़े गैर-दुश्मन जहाज, ईरानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बना सकते हैं, बशर्ते उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों में हिस्सा न लिया हो या उनका समर्थन न किया हो, साथ ही बताए गए सेफ्टी और सिक्योरिटी रेगुलेशन का पालन किया हो। मंत्रालय ने कहा कि स्ट्रेट में स्थायी सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए जरूरी है कि ईरान विरोधी सैन्य हमले और धमकियां बंद हों, अमेरिका और इजरायल की अस्थिर करने वाली गतिविधियां रुकें, और ईरान के वैध हितों का पूरा सम्मान किया जाए।

नाटो प्रमुख ने अमेरिकी हमलों का समर्थन किया,

ईरान के खतरे को लेकर चेतावनी दी

वॉशिंगटन, एजेंसी। नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया और चेतावनी दी कि ईरान ऐसी मिसाइल क्षमताएं विकसित करने के 'बहुत करीब' है जो यूरोप के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने यह बयान उस समय दिया जब नाटो हिंद महासागर में स्थित एक अमेरिका-ब्रिटेन सैन्य अड्डे पर लंबी दूरी के हमले की रिपोर्टों का आकलन कर रहा है। नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने फेस द नेशन पर बोलते हुए कहा कि नाटो अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सका है कि ईरान ने डियागो गार्शिया पर मिसाइल दागी है लेकिन यदि यह सच साबित होता है तो इसके गंभीर निहितार्थ होंगे। उन्होंने कहा, 'हम इस समय इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सच हुआ, तो यह इस बात का और सबूत होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं... वह बेहद महत्वपूर्ण है। 'रुट्टे ने कहा कि ईरान प्रमुख यूरोपीय शहरों पर हमला करने की क्षमता के करीब पहुंच रहा है। 'हमें यह निश्चित रूप से पता है कि वे उस क्षमता के बहुत करीब हैं,' उन्होंने ईरानी मिसाइलों की संभावित मारक क्षमता का जिक्र करते हुए कहा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान के पास परमाणु और मिसाइल दोनों क्षमताएं हो गईं, तो यह वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा बन जाएगा। 'अगर ईरान के पास परमाणु क्षमता होती है और वह मिसाइल क्षमता के साथ जुड़ जाती है, तो यह इज़राइल, क्षेत्र, यूरोप और वैश्विक स्थिरता के लिए एक सीधा और अस्तित्वगत खतरा होगा,' उन्होंने कहा।

नाटो प्रमुख ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि देरी महंगी साबित हो सकती है। उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, 'अगर हम बहुत लंबी बातचीत करते रहे, तो वह समय निकल सकता है जब इसे रोका जा सकता था।'

उनकी ये टिप्पणियां उस समय आईं जब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों की आलोचना की थी कि वे अमेरिकी अभियानों, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं।

रुट्टे ने इस नाराज़गी को स्वीकार किया लेकिन कहा कि अब सहयोगी देशों के बीच समन्वय शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 22 देशों जिनमें नाटो सदस्य और साझेदार जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रिलया और खाड़ी देश शामिल हैं, ने इस जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की पहल में हिस्सा लिया है।

उन्होंने कहा, 'इन तीन सवालों पर काम हो रहा ह-हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कहां चाहिए ताकि जलडमरूमध्य में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।'

रुट्टे ने यह भी बताया कि सैन्य तैनाती की समयसीमा अभी चर्चा में है और योजनाकार इस पर काम कर रहे हैं। 'सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है-कब,' उन्होंने कहा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी दबाव नाटो की एकता को प्रभावित कर सकता है, तो रुट्टे ने कहा कि संकट के समय गठबंधन हमेशा एकजुट हुआ है। उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर सहयोग और रक्षा खर्च बढ़ाने के फैसलों का भी उल्लेख किया।

यूक्रेन के मुद्दे पर, उन्होंने अमेरिकी कूटनीति का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और युद्ध के समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है।

'उन्हें इन सभी अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। यूक्रेन युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त करने का उनका प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है,' रुट्टे ने कहा।

शहबाज सरकार ने लग्जरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा संसाधनों से लदे कई वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमत में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 100 पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लग्जरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले इस ईंधन पर टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। बैठक में ईंधन कीमतों और आर्थिक राहत से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। इसमें कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तरार और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम : रिपोर्ट के अनुसार, हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमत में इस बढ़ोतरी का असर सार्वजनिक परिवहन और हवाई यात्रा के किराए पर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सरकार ने इससे पहले 6 मार्च को भी वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

यह उछाल अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण घरेलू ऊर्जा लागत पर दबाव बढ़ने से आया था। उस समय पेट्रोल की कीमत 266.17 रुपये से बढ़ाकर 321.17 रुपये प्रति लीटर कर दी गई थी, जबकि डीजल की कीमत 280.86 रुपये से बढ़ाकर 335.86 रुपये प्रति लीटर कर दी गई थी।

सरकार पहले भी बढ़ा चुकी है तेल की कीमतें : इस बढ़ोतरी की घोषणा पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। वहीं, 10 मार्च को जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस ने भी किराया बढ़ा दिया था। एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक, घरेलू उड़ानों के टिकट में 2800 से 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई, जो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और अन्य शहरों के लिए लागू है।

उड़ान के दौरान महिला की मौत, 13 घंटे शव के साथ यात्रा को मजबूर हुए यात्री

लंदन, एजेंसी। हांगकांग से लंदन जा रहे ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान में रविवार को एक महिला यात्री की मौत हो गई। उसकी उम्र 60 वर्ष के आसपास थी। महिला के शव को विमान के पीछे हिस्से में रख दिया गया जहां की फर्श गर्म थी। 13 घंटे से अधिक की उड़ान में शव से बदबू आने लगी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन पायलट ने आपात लैंडिंग कराने के बजाय यात्रा जारी रखी।

ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बीए32 के हांगकांग से उड़ान भरने के एक घंटे बाद ही महिला यात्री की मौत हो गई। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एयरबस ए350-1000 में चालक दल के सदस्यों के साथ 331 यात्री सवार थे। महिला की मौत के बावजूद पायलटों ने मार्ग बदलने या हांगकांग लौटने के बजाय हीथ्रो हवाईअड्डे तक यात्रा जारी रखने का फैसला किया। चालक दल के सदस्यों ने पहले शव को शौचालय में रखने पर विचार किया। बाद में शव को पीछे रसोई घर में ले जाया गया।

लैंडिंग के बाद 45 मिनट पुलिस ने की विमान की जांच : सूत्र के हवाले से फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया, कर्मचारियों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि रसोई घर का फर्श गर्म था। आरोप है कि गर्मी के कारण तीखी गंध उत्पन्न हुई और उड़ान के दौरान केबिन के पिछले हिस्से में फैल गई। कई यात्रियों ने विमान के उस हिस्से से दुर्गंध आने की शिकायत की। लैंडिंग के बाद पुलिस विमान में चढ़ी और सभी यात्रियों को अपनी सीटों पर बैठे रहने के लिए कहा। लगभग 45 मिनट तक पुलिस ने विमान की जांच की।

यात्री की मौत को नहीं माना जाता चिकित्सा आपातकाल : यात्री की मृत्यु को आमतौर पर चिकित्सा आपातकाल नहीं माना जाता है। शव को आमतौर पर बॉडी बैग में रखा जाता है या गर्दन तक कंबल से ढक दिया जाता है। यदि संभव हो तो शव को विमान के किसी कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जैसे कि खाली सीट या किसी अन्य अनुभाग में ले जाने का प्रयास किया जाता है। यदि उड़ान पूरी तरह से भरी हुई है तो शव को उसकी मूल सीट पर वापस रखा जा सकता है।

इमरान खान से बेटे कासिम ने की जेल में मुलाकात

पूर्व पीएम का सुनाया संदेश, कहा जजों को शर्म आनी चाहिए

इस्लामाबाद, एजेंसी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच उनके बेटे कासिम खान ने जेल में मुलाकात की है। उनकी सेहत बिगड़ने की खबरों के बीच इमरान खाने के बेटे सुलेमान और कासिम खान ने सरकार पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था। अब जेल में मुलाकात करने के बाद कासिम खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पिता का संदेश लोगों के सामने रखा है।

इमरान खान का संदेश

कासिम ने इमरान खान का संदेश बताते हुए लिखा, इस देश में जजों को शर्म आनी चाहिए। हम कई बार न्यायपालिका के पास गए लेकिन वे तो अपनी आत्मा बेच चुके हैं। उन्हें एकता और अखंडता की कोई परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि वे मुझे नहीं तोड़ सकते थे और इसलिए मेरी पत्नी को टारगेट करने लगे। इस तरह से आखिर बूशरा बीबी के साथ अमानवीय व्यवहार कैसे किया जा सकता है। यह सब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है।

इमरान खाने के हवाले से कासिम ने लिखा, मुझसे 30 मिनट की मुलाकात के लिए उन्हें 24 घंटे आइसोलेशन में रहना पड़ता है। किसी भी महिला को नुकसान पहुंचाना इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन उन लोगों का उद्देश्य हमें पता है। जिन जजों पर समाज में न्याय की जिम्मेदारी है, वही गद्दारी कर रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।

बता दें कि इमरान खान के दोनों बेटे लंदन में रहते हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पिता की दाहिनी आंख की रोशनी बेहद कम हो गई है और जेल प्रशासन उनका इलाज भी नहीं करवा रहा है। उन्होंने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में यहां तक कहा था कि उनका वीजा भी क्लियर नहीं हो रहा है। वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन सरकार को डर है कि इससे दुनिया का ध्यान इमरान खान की ओर चला जाएगा। हालांकि बाद में कासिम खान को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और वह जेल में इमरान खान से मुलाकात कर पाए।

बीते दिनों पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शीफा अंतरराष्ट्रीय अस्पताल में आंखों के उपचार के लिए स्थानांतरित करने की मांग की थी। खान पिछले साल अक्टूबर से दाहिनी आंख की बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं और उनका उपचार चल रहा है। सरकार के अनुसार, चिकित्सा उपचार के बाद उनकी आंख और दृष्टि दोनों में सुधार हुआ है। 72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं।

न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर विमान और ट्रक की टक्कर

न्यूयॉर्क , एजेंसी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग के समय रनवे पर एक फायर ट्रक से टकरा गया। यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल से आ रही थी।

हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ फायरफाइटर्स और विमान में सवार यात्री घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है। हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान और ग्राउंड वाहन दोनों को रुकने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी टक्कर हो गई।

इस घटना के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स रोक दीं और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात विमान ट्रक से टकराया। हादसे के बाद तुरंत लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। नोटिस के मुताबिक यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया। अब सवाल है कि आखिर इतने सुरक्षित एयरपोर्ट पर इस तरह का हादसा कैसे हो गया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जानकारी भी फायर फाइटर्स ने ही सबसे पहले दी थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।

लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा : शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर कनाडा का विमान एयरपोर्ट पर उतर रहा था। तभी रनवे पर खड़े एक ग्राउंड वाहन से उसकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद ही ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट पर अफरा-तफीर मच गई। तुरंत राहल बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

आखिर कैसे हुआ हादसा? : अब जांच अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का हादसा कैसे हो गया। जाहिर सी बात है कि रनवे पर फायर ट्रक की मौजूदगी और उधर विमान का लैंड करना एक असामान्य घटना है। अधिकारियों का कहना है कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी चूक की वजह से ऐसा हुआ या फिर किसी की लापरवाही की वजह से। एयर कनाडा, एफएए और न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने फिलहाल इस हादसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि ला गार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का एक बड़ा एयरपोर्ट है जहां से बड़ी संख्या में घरेलू विमानों का संचालन होता है। इस एयरपोर्ट के कुछ समय के लिए बंद होने से भी हवाई यातायात पर बड़ा फर्क पड़ेगा।

यूएस ने दी ग्लोबल वॉर्निंग, ईरान समर्थक बना सकते हैं अमेरिकियों को निशाना

वाशिंगटन , एजेंसी। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगाह किया है कि ईरान समर्थक अमेरिका के नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

क्या है चेतावनी : अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लिखा, 'विदेश मंत्रालय दुनिया भर में, और विशेष रूप से मिडल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। विदेश में रह रहे अमेरिकियों को पास के अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा चेतावनियों का पालन करना चाहिए। हवाई क्षेत्र के समय-समय पर बंद होने के कारण यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं।' आगे कहा गया, 'मिडल ईस्ट के बाहर स्थित अमेरिकी राजनयिक केंद्रों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान समर्थक समूह दुनिया भर में अन्य अमेरिकी हितों, ठिकानों या अमेरिकियों को निशाना बना सकते हैं।'

युद्ध चलते रहने के संकेत : अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने रविवार को कहा कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसकी किलेबंदी को तबाह करना है। ट्रंप अमेरिका के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी होंगे, उठाएंगे।

बेसेंट ने रविवार को एनबीसी के 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में कहा कि इन लक्ष्यों में ईरान की वायुसेना और नौसेना को नष्ट करना, उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने की उसकी क्षमता को खत्म करना शामिल है।

बेसेंट ने कहा, होर्मुज के किनारे ईरानी किलेबंदी को कमजोर करने के लिए सैन्य संपत्तियों का उपयोग करने का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक वे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाते। कभी-कभी आपको तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है।

तेल की कीमतें बढ़ेंगी : युद्ध के चौथे सप्ताह में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में नियमित गैसोलीन की औसत कीमत एक महीने पहले की तुलना में 34% अधिक है। यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतें 175 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं।

बेसेंट ने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि 50 दिनों तक कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ी रहेंगी। लेकिन इसके बदले में 50 वर्षों तक परमाणु हथियार वाले ईरानी शासन का खतरा नहीं रहेगा। कीमतें फिर कम हो जाएंगी। तेल की कीमतें कब तक कम होंगी, इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, मुझे नहीं पता कि इसमें 50 दिन लगेंगे या सौ दिन लगेंगे?

युद्ध के बीच ट्रंप-नेतन्याहू से बोले पहलवी: ईरान इस्लामी गणराज्य नहीं, मौजूदा शासन को उखाड़ फेंके

तेहरान, एजेंसी। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान इस्लामिक गणराज्य नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान में मौजूदा शासन को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि वे केवल शासन और दमन करने वाले तंत्र को ही निशाना बनाएं। उन्होंने अनुरोध किया कि आम जनता की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए।

क्या बोले रजा पहलवी ?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में पहलवी ने लिखा कि ईरान का बुनियादी ढांचा वहां के लोगों का है। यह आजाद ईरान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा इस्लामी गणराज्य का ढांचा दमन और आतंक का वह तंत्र है जिसका इस्तेमाल उस भविष्य को साकार होने से रोकने के लिए किया जाता है। ईरान की रक्षा की जानी चाहिए। इस शासन को उखाड़ फेंकना होगा।

पहलवी ने आगे कहा मैं राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से आग्रह करता हूं कि वे शासन और उसके दमनकारी तंत्र को निशाना बनाना जारी रखें, जबकि ईरानियों को अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक नागरिक ढांचे को बख्श दें। अमेरिका और इस्राइल के समर्थन से, और सबसे बढ़कर ईरानी

देशभक्तों के बलिदान से, ईरान की स्वतंत्रता का समय निकट है। ईरान जिंदाबाद!

कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले

इसी बीच, खाड़ी देश कुवैत ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अल जजीरा के अनुसार, कुवैत की सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि वहां सुनाई दे रहे धमाकों की आवाजें मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की वजह से आ रही हैं। सेना ने आम लोगों से अपील की है कि वे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

इस्राइली सेना ने बरामद किए टैंक रोधी मिसाइल

दूसरी तरफ, इस्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है। इस्राइली सेना ने बताया कि उनके सैनिकों ने वहां एक टैंक रोधी मिसाइल पोस्ट और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सेना ने सोशल मीडिया पर इन हथियारों की तस्वीरें भी साझा की हैं।

यूएई पर भी जारी हैं हमले

ईरान की तरफ से हुए मिसाइल हमलों के बाद इस्राइल के दक्षिणी और मध्य इलाकों में मिसाइलों के टुकड़े गिरने की खबरें मिली हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कई जगहों पर यह मलबा गिरा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का रक्षा मंत्रालय भी ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों का सामना कर रहा है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सुनाई देने वाली आवाजें मिसाइलों को रोकने की वजह से हैं। उनके लड़ाकू विमान और रक्षा प्रणालियां इन खतरों को लगातार नाकाम कर रही हैं।

आईसीसीस टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में स्मृति मंधाना का जलवा बरकरार, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को फायदा

दुबई (एजेंसी)। इंटरनेशनल क्रिकेट कार्उंसिल की मंगलवार को ताजा महिला टी20 रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा बनाए हुए है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी रैंकिंग में हल्की बढ़त मिली है। हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला टी20 बल्लेबाज की ताजा रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंच गईं। पहले वह 13वें स्थान पर थीं।

गेंदबाजी में स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर रैंकिंग में भी तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना के अलावा शैफाली वर्मा टॉप 10 में शामिल दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। वह छठे नंबर पर काबिज हैं जबकि जेमिमा रोड्रिग्स संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जॉर्जिया वोल पहली बार बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल हो गईं, जबकि न्यूजीलैंड की स्टार सोफी डिवाइन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक की मदद से सूची में दो पायदान ऊपर चढ़कर 18वां स्थान हासिल किया।

वहीं रैंकिंग के इस ताजा अपडेट में वेस्टइंडीज में हुई सीरीज के पहले दो मुकाबलों को भी शामिल किया गया है। इसमें रवांडा की 15 साल की फैनी उटागुशिमानिंदे भी 66वें स्थान पर रैंकिंग में शामिल हो गईं। वह टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला और इस फॉर्मेट में शतक लगाने वाली दोनों में से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं।

मियामी ओपन जैनिक सिनर ने तीसरे राउंड में जीत के साथ तोड़ा जोकोविच का रिकॉर्ड

मियामी (एजेंसी)। इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने मियामी ओपन में इतिहास रच दिया है। उन्होंने एकतरफा मुकाबले में कोरेंटिन मौटेट के खिलाफ 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ सिनर ने एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार 26 सेट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस मामले में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। नोवाक जोकोविच के नाम एटीपी मास्टर्स 1000 में लगातार 24 सेट जीतने का रिकॉर्ड था। सिनर ने इससे पहले टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में जीत दर्ज करते हुए जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। मैच के बाद उन्होंने कहा कि वे अपनी फॉर्म से खुश हैं और हर मैच में ध्यान बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सिनर का यह सिलसिला पिछले नवंबर में पेरिस मास्टर्स से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने बिना कोई सेट गंवाए खिताब जीता था। उन्होंने मार्च में भी शानदार फॉर्म को जारी रखा और पैरिबास ओपन में भी अपने दमदार प्रदर्शन को दोहराया। एटीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, मियामी में अपनी दो जीत की वजह से सिनर अब लगातार 13 मास्टर्स 1000 मैच जीत चुके हैं। अब उनका अगला मुकाबला अमेरिका के युवा खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन से होगा, जिन्होंने एलेजांद्रो टैबिलो को हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। सिनर का लक्ष्य 2017 में रोजर फेडरर के बाद 'सनशाइन डबल' हासिल करने वाले खिलाड़ी बनने का होगा। रैंकिंग की बात करें तो सिनर इस समय वर्ल्ड नंबर 1 की रेस में कार्लोस अल्काराज (स्पेनिश खिलाड़ी) के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कार्लोस को रविवार को तीसरे राउंड में सेबेस्टियन कोर्डा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। एक अन्य मुकाबले में अमेरिका के फ्रांसेस टियाफो ने डिफेंडिंग चैंपियन जैकब मेंसिक को कड़े मैच में 7-6(4), 4-6, 7-6(11) से हराया। 28 साल के टियाफो मियामी में पांचवीं बार और 2022 के बाद पहली बार चौथे राउंड में पहुंचे हैं। दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी का अगला मैच फ्रांसीसी खिलाड़ी टेरेंस एटमेन से होगा, जिन्होंने कनाडाई टेनिस प्लेयर फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को 6-3, 1-6, 6-3 से हराया था।

यौन शोषण के आरोपों में घिरा आरसीबी खिलाड़ी आईपीएल2026 से बाहर

बेंगलुरु (एजेंसी)। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले एक बड़ा झटका लगा है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को पुष्टि की कि तेज गेंदबाज यश दयाल निजी कारणों से पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे। दयाल का ट्रेनिंग सेशन से बाहर रहना और टीम बस के पोस्टर पर उनकी तस्वीर का न होना, पहले ही उनके बाहर होने की अफवाहों को हवा दे चुका था। कई लोग सोच रहे थे कि आखिर यह गेंदबाज है कहां। अब RCB के क्रिकेट डायरेक्टर, मो बोबाट ने उनके बाहर होने से जुड़े सभी संदेहों को दूर कर दिया है।

बोबाट ने यह भी कहा कि भले ही दयाल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, फिर भी वह टीम के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने रहेंगे। टीम मैनेजमेंट इस मुश्किल समय में भी खिलाड़ी का पूरा साथ देता रहेगा। उन्होंने कहा, 'तो, मैं बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि यश टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वह इस समय एक निजी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि हमने अब तक यश का पूरा साथ दिया है। इस बात का सबूत यह है कि जब हमारे पास खिलाड़ियों को रिटेन करने या रिलीज़ करने का विकल्प था, तब भी हमने यश को रिटेन किया था।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम उन्हें रिटेन करना चाहते थे। वह अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैं और आने वाले कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्ट में ही बने रहेंगे। हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। मैंने आज उनसे पहले भी बात की थी, लेकिन यह तय किया गया है कि इस समय उनका हमारे साथ जुड़ना न तो उनके अपने हित में है और न ही फ्रैंचाइजी के हित में। हमारा समर्थन उनके साथ बना रहेगा, और वह अभी भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं; जैसे-जैसे वह अपनी निजी मुश्किलों से गुज़रेंगे, हम उनसे बातचीत जारी रखेंगे।'

दयाल, जिन्होंने हाल ही में एक निजी समारोह में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता पुंडीर से शादी की है, पिछले कुछ समय से कई बड़े विवादों के केंद्र में रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया गया था क्योंकि वह एक ऐसे मामले में शामिल थे जिसमें उन पर कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। यह विवाद जुलाई 2025 में तब शुरू हुआ, जब उन पर शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित तौर पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दायर किया गया। बाद में जयपुर में उनके खिलाफ POSCO एक्ट के तहत एक और मामला सामने आया। इस बीच, RCB IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ करेगी।

हम केवल शामिल होने नहीं खिताब जीतने उतरेंगे : शुभमन

-अपने पर भरोसा होने के कारण बने रहते हैं शांत

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबलों में कठिन हालातों में भी शांत बने रहते है। शुभमन से जब इसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पर भरोसा है इसलिए व धैर्य से अपने अनुसार खेलते रहते हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी टीम के साथ सुरक्षित महसूस होता है। गुजरात ने एक बार खिताब जीता है जबकि एक बार वह उपविजेता रही है ऐसे में अब शुभमन का लक्ष्य टीम को इस बार जीत दिलाना रहेगा। उनका कहन है कि हम केवल भाग लेने नहीं जीतने के इरादे से उतरेंगे।

गिल ने में कहा, 'मैं स्वयं जैसा हूं और मेरे खेल और अपने समूह में जो विश्वास और सुरक्षा है, उसी से मेरे खेल में संयम आता है।' गुजरात टाइटंस की टीम अपना पहला मुकाबला 31 मार्च को गत उपविजेता पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद उसे 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है।

शुभमन ने कहा, 'किसी भी हालात में शांत रहने से ही खेल आगे बढ़ने पर जीत की संभावना बनी रहती है।।' उन्होंने कहा कि मुख्य कोच आशीष नेहरा से उन्हें ये सीखने को मिला है।

पिछले सत्र में गुजरात को एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था। नेहरा ने कहा कि इस बार उनका ध्यान केवल खिताब जीतने पर रहेगा। उन्होंने कहा, 'इस सत्र में अलग तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी सोचते हैं। उन्हें खेलना है, मैं बाहर बैठा हूं।'

नेहरा ने कहा, 'पहले दिन से हमारी नीति साफ है। हम केवल शामिल होने नहीं जीतने के लिए यहां हैं। एक नई टीम के लिए यह सोचना आसान होता है कि इसमें समय लगेगा पर हमारा कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा।' गुजरात के लिए सकारात्मक पक्ष आशीष नेहरा जैसा कोच होना है जो टीम को लगातार बेहतर करने प्रेरित करते रहते हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी

-मध्यक्रम के कमजोर होने से शीर्ष क्रम पर रहेगा दबाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल के इस सत्र में ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत के इरादे से उतरेगी। टीम अपने पिछले सत्र की गलतियों से सीखते हुए अपना पहला खिताब हासिल करना चाहेगी। टीम के लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं रहेगा। इसका कारण है कि उसका मध्यक्रम कमजोर है हालांकि शीर्ष क्रम के साथ ही तेज गेंदबाजी अच्छी है। पिछले सत्र में टीम 14 में से केवल 6 ही मैच पायी थी और प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच थी। इस बार प्रशंसकों को टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। निकोलसन पूरन और एडेन मार्करम के होने से लखनऊ का शीर्ष क्रम अच्छा है। मार्श और मार्करम ने पिछले सत्र में भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया था पर टीम के मध्य क्रम में कमजोरी नजर आती है। ऐसे में कप्तान ऋषभ के ऊपर जिम्मेदार बढ़ जाती है। उन्हें देखना होगा कि किस प्रकार टीम अधिक से अधिक रन बनाये। उनका साथ आयुष बदोनी, अब्दुल समद और शाहबाज अहमद जैसे बल्लेबाज देंगे। होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्जके से भी लखनऊ टीम को आईपीएल 2026 में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

लखनऊ का मजबूत पक्ष उनकी अच्छी तेज गेंदबाजी है। उसके पास आवेश खान, मोहम्मद शमी, मयंक यादव और एनरिक नॉर्टजे जैसे बल्लेबाज हैं। युवा मोहसन खान और प्रिंस यादव पर भी लोगों की नजरें रहेंगी। स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी दिग्वेश राठी के पास होगी। दिग्वेश ने पिछले सीजन अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया था। लखनऊ को उम्मीद करनी होगी की श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा फिट हो जायें।। हसरंगा अगर पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, तो टीम को काफी लाभ होगा।

वैभव सफल रहे तो रॉयल्स की जीत तय : अश्विन

मुम्बई । दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि अगर वह बड़ी पारी खेलता है तो राजस्थान रायल्स को जीत मिलनी तय है। वैभव ने गत वर्ष अपने पहले ही सत्र में आक्रामक बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया था। अब उम्मीद है कि इस नये सत्र में वह और भी बेहतर बल्लेबाजी करेगा। वैभव ने अंडर-19 विश्वप में भी कई अच्छी पारियां खेली थीं जिससे भी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में अश्विन कहा कहना है कि वैभव रॉयल्स के लिए किसी एक्स फैक्टर की तरह रहेगा। ऐसे में अगर वह क्रीज पर टिक गया तो रॉयल्स को बढ़े स्कारे स रोकना कठिन हो जाएगा। वैभव ने आईपीएल के अपने पहले सत्र में सात मैचों में 252 रन बनाते हुए 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की थी। इससे उनकी आक्रामक शैली का अंदाज होता है। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था। वह IPL इतिहास में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ हैं। अश्विन के अनुसार वह इस सीज़न में रॉयल्स के लिए मैच में अंतर ला सकते हैं। साथ ही कहा कि वह अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में है, इसलिए उस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना सही नहीं होगा।

अभी टीम के लिए काफी कुछ करना चाहता हूं : स्टोक्स

जून में क्रिकेट सत्र शुरु होने के बाद बेहतर प्रदर्शन रहेगा लक्ष्य

लंदन। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में टीम की करारी हार के बाद भी कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम को उनके पद पर बनाये रखा है। इससे पहले माना जा रहा था कि एशेज सीरीज में मिली 4-1 की हार के बाद कोच और कप्तान को को हटा दिया जाएगा। वहीं बोर्ड से मिले समर्थन से उत्साहित स्टोक्स ने कहा है कि वह वह अभी टीम के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं। जून में क्रिकेट सत्र शुरु होने के बाद उनका लक्ष्य और भी बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। स्टोक्स ने सोशल मीडिया में जारी एक बयान में, ' इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों देश का कप्तान होना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसे वह हल्के में इसे हल्के में नहीं लेते। साथ ही कहा कि कप्तानी करते हुए अच्छे और खराब दोनों ही प्रकार के अवसर आते हैं। इसमें कभी खुशी और कमी गम भी मिलता है। खेल आपको पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बस यही एक चीज़ है।' उन्होंने माना, पिछले 3 महीने मेरी कप्तानी के सफर का सबसे कठिन समय रहा है, इसने मुझे कई अलग-अलग तरीकों से परखा है और मुझे भरोसा है कि हर दूसरा कप्तान भी इससे गुजरा होगा। इसके बाद भी मैकलम, रॉब की और मुझमें इस टीम को आगे ले जाने का जुनून और इच्छा है, हम आपको वह सब कुछ देंगे जो हमारे पास है, हम जानते हैं कि हमने रास्ते में गलतियां कीं और हमने उन गलतियों से काफी कुछ सीखा है, आप सफलता से ज्यादा असफलताओं से सीखते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है पर सबसे जरूरी बात जो मैं प्रशंसकोंको बताना चाहता हूँ वह यह है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे यह टीम बहुत पसंद है, मुझे इंग्लैंड का कप्तान बनना बहुत पसंद है और मुझे इस भूमिका में देने के लिए बहुत कुछ है और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे कप्तानी का अवसर मिला।

बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए जारी किये दिशा निर्देश

-सभी खिलाड़ियों को करना होगा पालन

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये है। बोर्ड ने ये कदम इसलिए उठाया है जिससे खिलाड़ियों की मनमानी पर रोक लगायी जा सके। बीसीसीआई ने अपने नए आदेश में कहा है नये नियमों का पालन सभी को करना होगा। इसके तहत अब हर टीम के खिलाड़ी केवल टीम बस में ही यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा मैच के दिन किसी भी अभ्यास सत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी अलग इंतजाम किया है, जहां टीमों को मेन चौक के दोनों तरफ अभ्यास के लिए दो-दो विकेट दिए जाएंगे। इस दौरान कोई भी टीम विरोधी टीम को दिए गए अभ्यास विकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। टीम मैनेजर्स को नये दिशा निर्देशों की प्रति भेज दी हैं।

इसमें कहा गया है कि टीमों को प्रैक्टिस एरिया में 2 नेट और मेन स्क्वायर पर 1 साइड विकेट मिलेगा, जहां वे रेंज हिटिंग कर सकें। मुंबई वेन्यू के लिए, अगर दोनों टीमें एक ही समय पर अभ्यास कर रही हैं, तो हर टीम को 2 पिचें मिलेंगी। वहीं कोई भी ओपन नेट अलाउड नहीं होगा। अगर कोई टीम अपना अभ्यास जल्दी खत्म भी कर लेती है तब भी दूसरी टीम को उस पिच का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। मैच के दिनों में किसी अभ्यास की अनुमति नहीं होगी।मैच वाले दिन मेन चौक पर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। अभ्यास के दौरान केवल मान्यता प्राप्त स्टाफ को ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले में आने की अनुमति रहेगी। खिलाड़ी के परिवार के सदस्य और दोस्त अलग गाड़ी में सफर कर सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी एरिया से टीम का अभ्यास देख सकते हैं। एक्सटेंडेड सपोर्ट स्टाफ (थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट/नेट बॉलर) के लिए सूची बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद, नॉन-मैच डे एक्रेडिटेशन जारी किए जाएंगे। खिलाड़ी अभ्यास के लिए आते समय टीम बस का इस्तेमाल करेंगे। टीमें दो बैच में सफर कर सकती हैं।

इसके अलावा मैच के दिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया से मान्यता प्राप्त स्टाफ के लिए मैच वाले दिन अपना एक्रेडिटेशन लाना जरूरी है। पहली बार एक्रेडिटेशन न लाने पर चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार, टीम पर पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा। हिटिंग नेट देने के बाद भी, खिलाड़ी एईडी बोर्ड पर हिट करते रहते हैं जिसकी अनुमति नहीं रहेंगी। खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ एलईडी बोर्ड के सामने न बैठें। लाड़ी ऑरेंज और पर्पल कैप पहनेंगे। प्रेजेंटेशन में फ्लॉपी और स्लीवलेस जर्सी पहनने की इजाजत नहीं है। ऐसा न करने पर पहली बार में चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार, पैसे का जुर्माना लगेगा। मैच के दिनों में केवल 12 एक्रेडिटेड सपोर्ट स्टाफ को ही इजाज़त होगी, जिसमें टीम डॉक्टर भी शामिल हैं। जर्सी नंबर में बदलाव की जानकारी एकदिन पहले देनी होगी।

अलेक्जेंडर ओवेचकिन ने आईस हॉकी में अपना एक 1000वां गोल दागा

वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कैपिटल्स के अलेक्जेंडर ओवेचकिन रविवार को एनएचएल के रेगुलर सीजन और प्लेऑफ, दोनों को मिलाकर एक हजार गोल करने वाले दूसरे पुरुष आइस हॉकी खिलाड़ी बन गए। 40 साल के इस खिलाड़ी ने लीग में सबसे आगे चल रही टीम, कोलोराडो एवलांच के खिलाफ मैच के तय समय में 5-43 मिनट बाकी रहते हुए, एक पावर प्ले के दौरान यह ऐतिहासिक गोल किया। लेकिन इसके बावजूद वॉशिंगटन अतिरिक्त समय में 3-2 से हार गया। यह इस सीजन में ओवेचकिन का 26वां रेगुलर-सीजन गोल था और उनके करियर का कुल 923वां गोल था, जिससे उनका रिकॉर्ड और भी मजबूत हो गया। यह उपलब्धि उस समय के लगभग एक साल बाद हासिल हुई है, जब इस महान आइस हॉकी खिलाड़ी ने एनएचएल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में वेन ग्रेट्स्की को पीछे छोड़ दिया था। तीन बार के ओलंपियन ओवेचकिन अब ग्रेट्स्की के कुल एनएचएल गोलों के रिकॉर्ड के और भी करीब पहुंच गए हैं। इस महान कनाडाई खिलाड़ी ने अपने करियर का समापन कुल 1,016 एनएचएल गोलों के साथ किया था- जिनमें से 894 गोल रेगुलर सीजन में और 122 गोल प्लेऑफ में किए गए थे। प्लेऑफ में किए गए गोलों का यह रिकॉर्ड आज भी ग्रेट्स्की के नाम पर ही दर्ज है। वॉशिंगटन कैपिटल्स को अभी रेगुलर सीजन के 11 मैच और खेलने हैं, और फिलहाल उनका रिकॉर्ड 35-27-9 का है। एलेक्स ओवेचकिन ने वेन ग्रेट्स्की के 31 साल पुराने एनएचएल करियर गोलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

पाकिस्तान के फरहान को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला

दुबई । हाल में हुए टी20 विश्वकप में शानदार प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने फरवरी माह का आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। इसी के साथ ही फरहान नवंबर 2024 में हारिस रऊफ के बाद यह अवॉर्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। फरहान ने दो शतक के साथ ही आईसीसी टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में एक ही सत्र में दो शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। फरहान इस पूरे टूर्नामेंट में पाक की ओर से रन बनाने वाले अकेले खिलाड़ी रहे। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्तर के मुकाबले के अलावा श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था। फरहान ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक कुल 383 रन बनाये। उन्होंने कहा, 'आईसीसी टी20 विश्व कप में अवॉर्ड जीतना एक सुखद अहसास है। दुनियाभर के प्रशंसकों ने इससे देखा था जिससे इसमें अवार्ड जीतना खास रहा है।'

सैफ अंडर20 चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम मालदीव पहुंची, पाकिस्तान से होगा पहला मैच

माल। भारत की अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम सैफ चैम्पियनशिप में भाग लेने यहां पहुंच गई है और पहले मैच में बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से खेलेगी। इस मैच के बाद ग्रुप बी में भारतीय टीम का सामना 28 मार्च को बांग्लादेश से होगा । दोनों मैच नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और भूटान की टीमें हैं। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी जो एक अप्रैल को होगा। फाइनल तीन अप्रैल को खेला जाएगा। भारत के अंडर 20 मुख्य कोच महेश गवली ने कहा, 'यह काफी अहम और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। सभी टीमें काफी प्रतिस्पर्धी है और हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।'

भारतीय टीम - गोलकीपर : अल्साबित एसटी, प्रणव सुंदरमन, सूरज सिंह

डिफेंडर : बूंगसोन सिंह टी, जोडरिक अब्रांचेस, करीश सोराम, मालेमंगांबा सिंह थोकचोम, मोहम्मद कैफ, रोशन सिंह थांगजाम, उशाम सिंह, याइफारेम्बा चिंगाखाम

मिडफील्डर : अनिकेत यादव, डैनी मेतेइ लैशराम, गुरनाज सिंह ग्रेवाल, मोहम्मद अरबाश, रिषिकांता मेतेइ लैशराम, रिषि सिंह एन

फॉरवर्ड - उमंग दोडुम, प्रशान जाजो, रोहेन सिंह, विशाल यादव, सैमसन ए, तनवीर डे

थॉमस कप में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे ऑल-इंग्लैंड के उपविजेता लक्ष्य सेन

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट में उपविजेता रहे लक्ष्य सेन अगले महीने होने वाले थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम की अगुवाई करेंगे जबकि पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु और उभरती हुई स्टार उन्नति हुड्डा उबर कप में भारतीय चुनौती पेश करेंगे।

भारतीय बैडमिंटन संघ ने 2022 में थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीम के खिलाड़ियों को काफी हद तक बरकरार रखा है। उसने 24 अप्रैल से तीन मई तक डेनमार्क के होर्सेंस में होने वाली प्रतियोगिता के लिए सेन, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय तथा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को टीम में बनाए रखा है। युवा शटलर आयुष शेट्टी को सीनियर स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद पहली बार टीम में जगह मिली है।

पुरुष टीम में 2022 की खिताब विजेता टीम के सदस्य एमआर अर्जुन की भी वापसी हुई है, जिन्होंने चोट से उबरकर नए खिलाड़ी हरिहरन अमसाकरुनन के साथ युगल टीम में जगह बनाई है। 2022 की युगल टीम के सदस्य ध्रुव कपिला भी टीम का हिस्सा हैं जबकि किरण जॉर्ज एकल में अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेंगे। उबर कप में 2019 की विश्व चैंपियन सिंधु, शीर्ष युगल जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली के साथ मिलकर भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगी।

भारतीय टीम पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसका लक्ष्य इस बार अपने इस प्रदर्शन में सुधार करना होगा। उन्नति हुडा के साथ देविका सिहाग, इशारानी बरुआ और किशोरी तन्वी शर्मा जैसी युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी टीम में शामिल है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'टीम का चयन 10 मार्च तक की बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग के आधार पर किया गया है, जिसमें शीर्ष पांच एकल खिलाड़ी और शीर्ष दो युगल जोड़ियां शामिल हैं। टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो जैसे खिलाड़ियों को युगल में उनके अनुभव के कारण टीम में जगह मिली है।'

भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा ने कहा, 'हमारी

दोनों टीमों में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। सीनियर खिलाड़ी स्थिरता लाते हैं और युवा खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने दिखाया है कि वे इस स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे हमें टूर्नामेंट में उतरने से पहले आत्मविश्वास मिलता है।' उन्होंने कहा, 'महिला टीम में देविका सिहाग का चयन इस साल की शुरुआत में थाईलैंड मास्टर्स में खिताब जीतने के बाद हुआ है, जबकि इशारानी बरुआ ऑरलियन्स मास्टर्स में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद टीम में शामिल हुई हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा का खेल लगातार बेहतर होता जा रहा है।'

भारतीय टीम इस प्रकार है

पुरुष : लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत, एच.एस. प्रणय, किरण जॉर्ज, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्सकरुनन, एम. आर. अर्जुन, ध्रुव कपिला।

महिला: पीवी सिंधु, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, देविका सिहाग, इशरानी बरुआ, ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, तनीषा क्रास्टो।

डबल हीरो पीरियड ड्रामा फिल्म है धनुष की 'वेलपारी'

साउथ इंडस्ट्री में इन दिनों चर्चा है कि निर्देशक एस शंकर सा अपनी लंबे समय से अटकी ऐतिहासिक परियोजना 'वेलपारी' के लिए धनुष से संपर्क में हैं। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री सूत्रों का दावा है कि डेट्स और अवेलिबिलिटी को लेकर शुरुआती स्तर पर बातचीत संभव है।

दो हीरो वाले नैरेटिव में मेकर्स रचेंगे बड़ा कैनवास

'वेलपारी' को शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसे एक डुअल-हीरो पीरियड ड्रामा के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इससे पहले रिपोर्ट्स में विक्रम और रणवीर सिंह के नाम प्रमुख पात्रों के लिए सामने आए थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब चर्चा है कि शंकर ने धनुष की डेट्स के बारे में जानकारी ली है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। हाल ही में शंकर, धनुष की फिल्म 'डी55' के पूजा समारोह में शामिल हुए थे। 'DSS' को प्रोड्यूस कर रहे बैनर आर टेक स्टूडियोज, 'वेलपारी' को लेकर शंकर से बातचीत में हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

'वीर युग नायकन वेलपारी' पर आधारित है कहानी

शंकर की यह फिल्म फेमस नॉवेल 'वीर युग नायकन वेलपारी' पर आधारित है, जिसे लेखक सु वेंकटेशन ने लिखा है। यह नॉवेल प्राचीन तमिल शासक वेलपारी के जीवन, शौर्य और अद्भुत दानवीरता का वर्णन करती है।

शंकर पहले भी सार्वजनिक मंचों पर नॉवेल के प्रति अपनी गहरी इच्छा जता चुके हैं और इसे 'गेम ऑफ थ्रोन्स' और 'अवतार' जैसे भव्य स्तर पर बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। दूसरी ओर, धनुष हाल ही में 'तेरे इश्क में' में नजर आए थे और अब 'कारा' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्मों में 'डी55', 'डी56' और 'कलामः द मिसाइल मैन और इंडिया' शामिल हैं। ऐसे में अगर 'वेलपारी' पर मुहर लगती है तो यह तमिल सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकती है।

थ्रिलर जैसे जॉनर में काम करना आसान नहीं होता

गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार नए साल के स्वागत का प्रतीक है और नई उम्मीदें लेकर आता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस दिन की खुशियों का हिस्सा बनता है। इस कड़ी में अभिनेत्री स्नेहलता वसईकर ने बातचीत में गुड़ी पड़वा के महत्व और अपने निजी अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यह त्योहार उनके दिल के बहुत करीब है। बचपन में सुबह जल्दी उठकर गुड़ी लगाने की परंपरा, पारिवारिक मिलन और त्योहार की तैयारियां उनकी सबसे प्यारी यादें हैं।

स्नेहलता ने कहा, ''गुड़ी पड़वा मुझे नए साल की नई उम्मीदें देता है। इस साल मेरे लिए गुड़ी पड़वा और भी खास है, क्योंकि यह पेशेवर रूप से मेरे लिए एक नया चरण लेकर आया है। मैं जल्द ही थ्रिलर शो 'वशीकरणम' में मुख्य किरदार सुमन के रूप में नजर आने वाली हूं। यह किरदार मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों है।'' स्नेहलता ने कहा, ''गुड़ी पड़वा की तरह हर नई शुरुआत जीवन में सकारात्मक बदलाव और नए अवसर लेकर आती है। इस उत्सव का संदेश सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि आशा और नए अनुभवों को अपनाने का भी है। यही सोच मैं अपने पेशेवर जीवन में भी लागू कर रही हूं। 'वशीकरणम' मेरे लिए सिर्फ एक नया शो नहीं है, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है, जिसे मैं उत्साह और समर्पण के साथ निभा रही हूं।'' स्नेहलता ने आगे कहा, ''थ्रिलर जैसे जॉनर में काम करना आसान नहीं होता। इस तरह के शो में अभिनय करते समय भावनाओं और एक्सप्रेशन पर मजबूत पकड़ होना बेहद जरूरी है। हर सीन को खास बनाने के लिए अभिनेता को पूरी तरह उस पल में डूबना पड़ता है। इस तरह के अनुभव से अभिनय में गहराई आती है और दर्शकों के लिए किरदार ज्यादा विश्वसनीय बनता है।''

स्नेहलता वसईकर मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय से एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने कई क्षेत्रीय फिल्मों और शो में काम किया है और अपने अभिनय की वजह से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। उनके लिए 'वशीकरणम' शो टीवी में डेब्यू प्रोजेक्ट है।

वेब सीरीज 'सपने vs एवरीवन' में नजर आएंगी खुशाली कुमार

फिल्म 'घुड़चढ़ी' में रवीना टंडन और संजय दत्त के साथ अभिनय कर चुकीं खुशाली कुमार अब फिल्मों के बाद जल्द ही ओटीटी पर अपना डेब्यू करने वाली हैं। यह सीरीज का दूसरा भाग होगा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा। फैशन और म्यूजिक वीडियो से शुरुआत करने वाली खुशाली अब फिल्मों और वेब सीरीज पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। खुशाली कुमार वेब सीरीज 'सपने vs एवरीवन' के सीजन 2 में नजर आएंगी। इस सीरीज में खुशाली 'तृप्ती' नाम की लड़की की भूमिका में नजर आएंगी। इस सीरीज को लेकर खुशाली काफी उत्साहित हैं। हाल ही में मुंबई में एक इवेंट में खुशाली ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सपने सच होने जैसा लग रहा है। पहली बार ओटीटी पर काम करना उनके लिए बहुत खास और भावुक अनुभव है।

खुशाली कुमार कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। उन्हें आखिरी बार संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म 'घुड़चढ़ी' में देखा गया था। इसके अलावा वह 'धोखाः राउंड डी कॉर्नर', 'स्टारफिश',, 'डेढ़ बीघा जमीन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने टी-सीरीज के कई लोकप्रिय संगीत वीडियो जैसे 'मैनु इश्क दा', 'हाईवे स्टार', और 'रात कमाल है' में भी काम किया है।

'धुरंधर 2' की आड़ में रामगोपाल वर्मा ने नामी एक्टर्स पर साधा निशाना

गुरुवार को फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों रिलीज हुई, इसने पहले दिन ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है। रणवीर सिंह के करियर की भी यह सबसे बड़ी हिट बन गई है। फिल्म को आदित्य धर ने निर्देशित किया है। इस फिल्म को देखकर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा गदगद हैं। साथ ही वह बॉलीवुड के बाकी फिल्ममेकर्स और एक्टर को भी एक चेता रहे हैं। एक ट्वीट करते हुए पहले रामगोपाल वर्मा ने भारतीय सिनेमा के फिल्ममेकर्स को निशाने पर लिया। वह अपने ट्वीट में लिखते हैं, 'धुरंधर 2 उन सभी फिल्म निर्माताओं के लिए एक डरावनी फिल्म है जिन्होंने घटिया सिनेमा पर अपना करियर और दौलत बनाई। वो सिनेमा जो शोर-शराबे और मसाले से भरा हुआ, हमारे गले में जबरदस्ती उतारा गया था, अब जल्द ही वेंटिलेटर पर सांस लेने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आएगा।'

आगे ट्वीट में रामगोपाल वर्मा ने बिना नाम लिए बड़े एक्टर्स को भी लताड़ा है। वह ट्वीट में लिखते हैं, ' फिल्म 'धुरंधर 2' उन सभी फिल्म निर्माताओं को बुरी तरह डरा देगी जो आज भी स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने उन सभी हीरोज को मार डाला है जो कभी खून नहीं बहाते, कभी दर्द महसूस नहीं करते हैं।' डायरेक्टर ने बॉलीवुड के उन हीरो को सर्कस का जोकर तक कह दिया है। रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में कई और बातें कही हैं। लेकिन आखिरी में वह 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर को जमकर सराहते हैं। वह ट्वीट में लिखते हैं, 'फिल्म 'धुरंधर 2' सिर्फ एक मूवी नहीं है। यह एक फैसला है। आदित्य धर ने उस तरह के सिनेमा का सिर काट दिया है, जिसने दर्शकों की समझ का अपमान किया है। जिसने कहानियों की जगह भड़कीले और दिखावटी विजुअल्स को दिखाया, जिसने हीरो को भगवान और दर्शकों को भेड़ बना दिया।

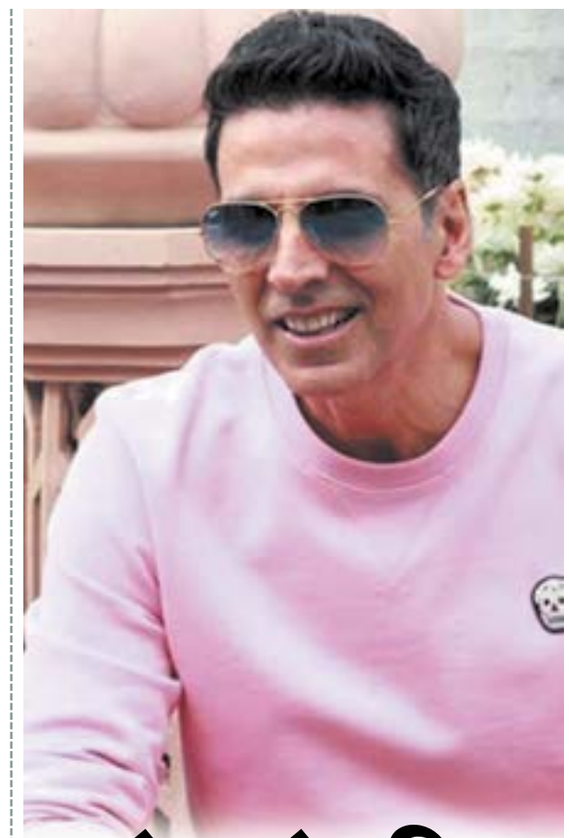

इमेज के लिए नहीं करता देशभक्ति फिल्में

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपनी कनाडाई नागरिकता पर खुलकर बात की है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अक्षय ने बताया कि उन्होंने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला तब लिया था, जब उनकी बैक-टू-बैक 16-17 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। अक्षय ने साफ किया कि वह देशभक्ति वाली फिल्में अपनी कोई खास इमेज बनाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वह विषय सही लगते हैं।

लगातार फिल्में फ्लॉप हुईं तो लिया था फैसला

अक्षय कुमार ने बताया कि उनके करियर में एक ऐसा दौर आया था जब उनकी 16-17 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थीं। अक्षय के मुताबिक, मेरे पास काम तो था लेकिन सिर्फ 3-4 फिल्में बची थीं। उस वक्त मुझे लगा कि अब कुछ और करना चाहिए। मुझे कनाडा में काम मिल रहा था, तो मैंने वहां जाकर छोटा सा बिजनेस करने का प्लान बनाया था। इसी दौरान अक्षय ने कनाडा की नागरिकता ली और उन्हें वहां का पासपोर्ट मिल गया। अक्षय ने कहा की कमाल की बात यह रही कि मेरी जो 3 फिल्में रिलीज होने वाली थीं, वो तीनों ही हिट हो गईं। मुझे फिर से भारत में काम मिलने लग गया। मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि मैं अब नहीं आ रहा हूं और भारत में ही रहूंगा। उस बीच मैं पासपोर्ट वाली बात भूल गया। मेरे लिए वह सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट था।

इमेज बनाने के लिए नहीं करता देशभक्ति फिल्में

जब अक्षय से पूछा गया कि क्या 'केसरी' जैसी फिल्में उन्होंने नेशनलिस्ट हीरो की इमेज बनाने के लिए कीं? इस पर उन्होंने कहा, मैं जो भी काम करता हूं, अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं करता। मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन देशभक्त की इमेज बनाने के लिए नहीं। मैं वो काम करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं ट्रोलिंग से बचने के लिए ऐसी फिल्में करता हूं, जबकि ऐसा नहीं है।

भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरा, फिर भी लोग बोलते हैं

ट्रोलिंग पर दुख जताते हुए अक्षय ने कहा, लोग मुझे कैनेडियन-कैनेडियन कहने लगे, तो मैंने पासपोर्ट ही बदल लिया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना क्यों बोलना चाहते हैं? वह सिर्फ एक पासपोर्ट था, जबकि मैं टैक्स भारत में भरता हूं। जब मैं कैनेडियन था, तब भी मैंने भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरा। मैंने कनाडा में कभी टैक्स नहीं भरा, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता।

2023 में मिली भारत की नागरिकता

अक्षय कुमार के पास लंबे समय तक कनाडा की नागरिकता रही, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता था। साल 2023 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्षय ने जानकारी दी थी कि उन्हें अब भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट मिल गया है। इससे पहले वे कनाडाई नागरिक होने के कारण भारत में वोट भी नहीं डाल पाते थे।

बड़े पैमाने पर शिवाजी की कहानी को दिखाना चाहते हैं रितेश

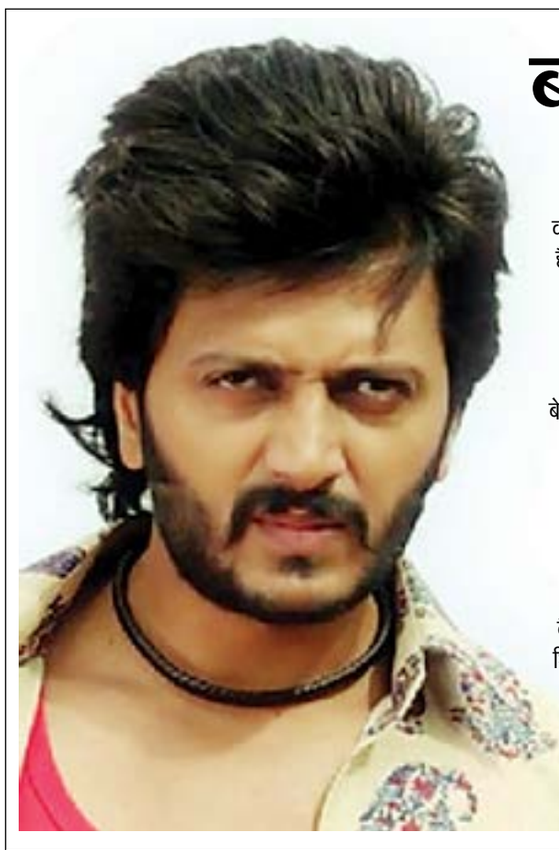

रितेश देशमुख अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म 'राजा शिवाजी' के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में 'धुरंधर 2' के साथ फिल्म का टीजर दिखाया गया, जिसे देखने के बाद फैंस इस फिल्म के लिए और भी उत्साहित हो गए हैं। अभिनेता-निर्देशक रितेश देशमुख के लिए यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई प्रयास से कहीं बढ़कर है। यह एक बेहद निजी सफर है, जो एक महाराष्ट्रीयन के रूप में उनकी जड़ों से जुड़ा है। उनका मानना है कि इस महान योद्धा राजा का किरदार निभाना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी की बात है।

छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं

वैरायटी से बात करते हुए रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक मराठी परिवार से होने के नाते, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां पढ़ते और सुनते हुए बड़े हुए हैं। उनकी प्रासंगिकता आज की पीढ़ी में भी उतनी ही सच्ची है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा है। मैं गुरुओं या देवताओं की बात नहीं कर रहा। मैं एक ऐसे राजा की बात कर रहा हूं, जो लगभग 350 साल पहले रहते थे, लेकिन आज भी लोग उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। वो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। एक ऐसे राजा जिन्होंने एक अमर विरासत छोड़ी है, जो आज भी प्रेरणा देती है। फिल्म को लेकर रितेश देशमुख ने कहा कि 'राजा शिवाजी' एक मराठी द्विभाषी फिल्म है। हम अन्य भाषाओं में भी फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। हमारा उद्देश्य इसे बड़े पैमाने पर बनाना है। अक्सर, मराठी फिल्में सीमित दायरे में ही बन पाती हैं। जनसंख्या के हिसाब से, महाराष्ट्र में लगभग 12 करोड़ लोग हैं, जिनमें से लगभग 10 करोड़ मराठी भाषी हैं। यह कई अन्य राज्यों या यहां तक कि देशों की जनसंख्या से कहीं अधिक है। हालांकि, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े इसे नहीं दर्शाते। क्षमता तो है ही, जैसा कि 'सैराट' (2016), 'लाई भारी' (2014) या 'वेद' (2022) ने दिखाया है। मैं महाराष्ट्र की व्यावसायिक क्षमता का लाभ उठाना चाहता हूं। शिवाजी महाराज को पूरे भारत में पूजा जाता है। हम चाहते हैं कि लोग देखें कि राजा के निर्माण में क्या-क्या शामिल था और उनके बचपन पर किन-किन चीजों का प्रभाव पड़ा।

हम एक नए पहलू को बताने की कोशिश कर रहे हैं

फिल्म की कहानी और शूटिंग अनुभव को लेकर अभिनेता ने कहा कि कहानी उनके एक साक्षी होने से शुरू होती है। फिर उनके प्रश्न पूछने तक और अंत में उनके द्वारा अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने तक जाती है। हम उनके व्यक्तित्व के एक बिल्कुल अलग पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। यह जितनी ऐतिहासिक गाथा है, उतनी ही यह एक परिवार की कहानी भी है। एक पिता, एक पुत्र, एक पति और एक भाई की कहानी। उनका 50 साल की कम उम्र में ही निधन हो गया, लेकिन तब तक उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। मैं उनके जीवन को ढाई-तीन घंटे में समेटने की कोशिश कर रहा हूं।

1 मई को रिलीज होगी 'राजा शिवाजी'

रितेश देशमुख ने 'राजा शिवाजी' में न सिर्फ अभिनय किया है, बल्कि इसे निर्देशित भी किया है, कहानी भी लिखी है और प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म में एक बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी, जिसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया देशमुख, फरदीन खान, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री और सलमान खान के नाम शामिल हैं।

दीव जिले की 3 ग्राम पंचायतों के नये पंचायत भवनों का हुआ उद्घाटनः सरपंचों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर शुरु किया कामकाज

■ महाराणा प्रताप ग्राम पंचायत, महारानी लक्ष्मीबाई ग्राम पंचायत और वणाकबारा ग्राम पंचायत को मिला नया भवन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दीव 24 मार्च।

दीव जिले की 3 ग्राम पंचायत को आज उनका नया पंचायत भवन मिल गया। तीनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने विधिवत पूजा-अर्चना करके नये पंचायत भवन में प्रवेश किया और लोगों के कार्य भी शुरु कर दिये। दीव जिले की महाराणा प्रताप ग्राम पंचायत, महाराणी लक्ष्मीबाई ग्राम पंचायत और वणाकबारा ग्राम पंचायत की नई पंचायत भवन का ब्राह्मणों द्वारा सरपंच मीनाक्षी जीवन, नरसिंह रामजी एवं वेलजी बिका ने अपनी-अपनी पंचायतों में पूजा करके प्रवेश किया। इसके साथ ही तीनों सरपंचों ने अपनी-अपनी पंचायत भवन में सरपंच की कुर्सी ग्रहण कर कामकाज भी शुरु कर दिया। इन नई पंचायत इमारतों में सरल सेवा केन्द्र, एटीएम एवं लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई है। दीव जिला की 3 नई ग्राम पंचायतों को नया पंचायत भवन मिलने पर तीनों सरपंचों ने प्रशासक प्रफुल पटेल के प्रति आभार जताया। पंचायत भवनों के उद्घाटन अवसर पर दीव एडीएम जतीन गोयेल, डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा, मामलतदार धर्मेश दमणिया मुख्य रुप से उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं महानुभावों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। साथ ही सरपंचों ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान एडीएम जतीन गोयेल और डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा ने भी सरपंचों को अभिनंदन दिया।

दानह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन सहकारी मंडली लिमिटेड की हुई बैठक

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 24 मार्च। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के प्रशासक प्रफुल पटेल के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण गुप्ता के मार्गदर्शन एवं जिला विकास एवं योजना अधिकारी पंकज एन. परमार की निगरानी में दानह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन सहकारी मंडली लिमिटेड के प्रमुख हितधारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज ग्राम पंचायत दपाडा में आयोजित की गई। यह बैठक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आयोजित प्रथम औपचारिक बैठक थी, जिसने क्षेत्र में सामूहिक योजना एवं कृषि विकास हेतु एक सशक्त आधार स्थापित किया। साथ ही जिला पंचायत के अधिकारियों एवं विकास से जुड़े कार्मिकों द्वारा भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजू महाला, फिरोज वाडिया अध्यक्ष तथा प्रशांत दलवी (सचिव) सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत सदस्य नवसू लिलेश डोडिया तथा ग्राम पंचायत दपाडा के सरपंच नागिन रूपजी वलवी भी उपस्थित रहे। साथ ही जिला पंचायत के चैतन्य कोंडेती (प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण विकास), मधुसूदन रेड्डी (जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएलएम) तथा प्रियंका भीमरा (एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो) सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका एवं उनके महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने तथा समग्र कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही अधिक से अधिक किसानों को एफपीओ से जोडने, सामूहिक क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न संस्थानों एवं बाजारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु प्रभावी रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक जिले में एफपीओ तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक एवं आशाजनक पहल है। यह सभी हितधारकों की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सतत विकास हेतु सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो दादरा नगर हवेली में समावेशी विकास एवं किसान सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सांझ पारडी के जय अगासी माता मंदिर का मनाया गया पाटोत्सव

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 24 मार्च। नानी दमण के सांझ पारडी स्थित जय अगासी माता मंदिर का 17वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरु हो गये थे। जय अगासी माता की पूजा आरती करने के बाद दोपहर को महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बडी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर जय अगासी माता के दर्शन किये और महाप्रसाद का लाभ लिया।

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच गैस संकट का फायदा, सूरत में कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़

■ एलसीबी की छापेमारी में 34 लाख से ज्यादा का माल जब्त, 8 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

सूरत (ईएमएस)। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन और गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे संवेदनशील समय में सूरत जिले के कुछ लालची तत्व इस मानवीय संकट को कमाई का जरिया बना रहे हैं। देशभर में घरेलू रसोई गैस की कमी का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सूरत जिला एलसीबी ने सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक सूरत पुलिस टीम पेट्रोलिंग के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर कामरेज तालुका के परब गांव स्थित 'ओम इंडस्ट्रियल एस्टेट' में छापा मारा, जहां गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण और बिक्री की जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 229 भरे हुए और 153 खाली गैस सिलेंडर, दो आयशर टेंपो, एक छोटा हाथी वाहन, मॉपेड बाइक, मोबाइल फोन और नकदी सहित कुल 34,18,622 रुपये का सामान जब्त किया। जांच में सामने आया कि यह गैस महाराष्ट्र के पालघर स्थित 'कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड' से भरकर लाई गई थी। नियमानुसार यह सिलेंडर परब, वेलंजा और अंकलेश्वर के ग्राहकों तक पहुंचने थे, लेकिन रामदेव गैस एजेंसी के देवीलाल कलाल ने अपने मालिक कन्हैयालाल के कहने पर इस स्टॉक को डायवर्ट कर दिया। आरोपी 900-1000 रुपये के सिलेंडर को 2350 रुपये तक ऊंचे दामों में बेच रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अधिकांश राजस्थान के निवासी हैं। ये लोग यहां बर्तन की दुकान या ड्राइविंग के बहाने इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में गोरख जगताप (ड्राइवर), देवीलाल कलाल, पवनकुमार मेवाड़ा, संपतराज मेवाड़ा, निर्मलकुमार मेवाड़ा, अनमोल राव, विष्णु राव और संतोष कलाल शामिल हैं। जबकि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कन्हैयालाल भंवरलाल कलाल फिलहाल फरार है, जिसे पुलिस ने वांछित घोषित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस गंभीर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कामरेज पुलिस को सौंप दिया है।

मोटी दमण उप कारागार में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 24 मार्च। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण दमण और एडवोकेट बार एसोसिएशन दमण के सहयोग से 25 मार्च को सुबह 10 बजे मोटी दमण उप कारागार में कानूनी जागरूकता का आयोजन किया जाएगा। इस कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य कानूनी सहायता बचाव वकील अल्पेशकुमार दमणिया समझौता ज्ञापन और कैदियों तथा विचाराधीन कैदियों के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वकील प्रिंस छीपा कार्यक्रम का संचालन करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पर जानकारी देंगे। वकील मयंक पटेल कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)
3rd and 4th Floor, Plot No. 55-56, Udyog Vihar, Phase-IV, Sector-18, Gurugram Haryana-122015
Ph. No. 0124-4684705 E-mail: secy.jerc.uts@gov.in Website: www.jercuts.gov.in

PUBLIC NOTICE
(Petition No. 165/2026 ,176/2026)

The following petitions have been filed for approval:

1. Petition No. 165/2026: Filing of Petition under Sections 61,62 and 64 of the Electricity Act, 2003 read with all the applicable Regulation, under the JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulation,2021 and the JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulation, 2024 for True up of FY 2024-25 for the Distribution Business of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
2. Petition No. 176/2026: Filing of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for Truing up of FY 2024-25 under Section 61,62 and 64 of the Electricity Act, 2003 for DNH & DD Power Corporation Limited.

The said petitions have been admitted. The above said petitions are available on the Commission's website i.e., www.jercuts.gov.in and on the respective website of the Petitioners as detailed below:

Petition No.	Petitioner	Website/Link
165/2026	DNH & DD Power Distribution Corporation Limited, 1st & 2nd Floor, Vidyut Bhawan, Next to Secretariat Building, 66kV Road, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu-396230	https://connect.torrentpower.com/tplcp/pages/download
176/2026	DNH and DD Power Corporation Ltd., Vidyut Bhavan,66 KV Road, Near Secretariat, Amli, Silvassa - 396230	www.dnhddpcl.in

Interested persons may give their objections/suggestions/comments on the above petitions, in person/registered post addressed to – The Secretary, JERC (for the State of Goa & Union Territories) 3rd & 4th Floor, Plot No. 55-56, Udyog Vihar, Phase-IV, Sector- 18, Gurugram, Haryana 122015 or through e-mail at mail id secy.jercuts@gov.in on or before 16th April 2026 with a copy to following:

1. For Petition No. 165/2026: General Manager, DNH & DD Power Distribution Corporation Limited, 1st & 2nd Floor, Vidyut Bhawan, Next to Secretariat Building, 66kV Road, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu-396230 (email id: connect.dnhdd@torrentpower.com)
2. For Petition No. 176/2026: Executive engineer, DNH and DD Power Corporation Ltd., Vidyut Bhavan,66 KV Road, Near Secretariat, Amli, Silvassa - 396230(email id: ee-elec-dnh@ddd.gov.in)

The Public Hearing in the above matters shall be held as per following details

a.	**On 09.04.2026 at 11.00 A.M.**	**Virtual Mode**. Any person who intends to participate in the virtual public hearing may intimate their mobile number and email-id to the Secretary, JERC on secy.jercuts@gov.in so that link for participation in the video conference on due date and time can be sent to them timely.
b.	**On 16.04.2026 at 11.00 A.M.**	**Physical mode at Daman**. Venue shall be published separately

CBC 34124/12/0040/2526

Rajesh Dangi, Secretary (I/c)

स्वामीः मारुतिनंदन पब्लिक, संपादक, प्रकाशक व मुद्रक विजय जगदीशचंद्र भट्ट द्वारा गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल, नानी दमण - 396210 से प्रकाशित तथा असली आजादी प्रेस गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल नानी दमण - 396210 से मुद्रित।
(समाचारों के चयन के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत संपादक की होगी। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दमण न्यायालय के अधीन होगा।)